चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 28 मार्च–03 अप्रैल 2016 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

मृत्यु प्रदेश!

फोटो-प्रभात पाण्डेय

मध्य प्रदेश में बन रहा किसानों की आत्महत्या का रिकॉर्ड

मध्य प्रदेश किसानों के लिए क्या मृत्यु प्रदेश बनता जा रहा है? मध्य प्रदेश में किसानों की ताबड़तोड़ हो रही आत्महत्याओं से यह सवाल गहरा गया है. इसके साथ कई और सवाल जुड़े हैं. किन समस्याओं की वजह से किसान सिलसिलेवार आत्महत्याएं कर रहे हैं? शिवराज सिंह सरकार किसानों तक मदद पहुंचाने में क्यों विफल रही है? सरकारी योजनाओं का फ़ायदा किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसे कई सवालों की पड़ताल करने के लिए चौथी दुनिया की टीम ने मध्य प्रदेश के कई प्रभावित इलाकों का दौरा किया और सुदूर गांवों तक जाकर किसान परिवारों से मुलाकात की, उनका हाल-चाल पूछा, ज़मीनी हक़ीक़त का जायजा लिया. तहकीकात में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिनका ख़ुलासा इस रिपोर्ताज में क्रमवार होता जाएगा और आपको किसानों की हताशा और उनकी त्रासदी का भयावह दृश्य दिखाई देगा, जिस पर अभी देश की निगाह नहीं है...

मनीष कुमार

किसानों की आत्महत्या के तथ्यात्मक आंकड़ों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार चाहे जितना कन्नी काटे और हेराफेरी करे, लेकिन सरकार और सामाजिक संस्थाओं के सर्वेक्षणों से जो तथ्य और परिणाम सामने निकल कर आ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक हैं. पिछले नौ महीने में अगर नौ सौ किसानों ने आत्महत्या कर ली, तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति कितनी भयावह है. किसानों की खुदकुशी का यह नौ सौ का आंकड़ा मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक स्वीकारोक्ति है. पिछले चार महीने में ही करीब साढ़े तीन सौ किसानों ने आत्महत्या कर ली है. मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री की तरफ से विधानसभा में यह आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया जा चुका है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी पिछले साल नवम्बर में यह कह चुके हैं कि उस एक साल में 1108 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी. सरकार और सामाजिक संस्थाओं के सर्वेक्षणों का औसत भी निकालें तो मध्य प्रदेश में हर साल आत्महत्या करने वाले किसानों की तादाद कम से कम एक हजार जरूर है. शर्मनाक पहलू यह है कि कुछ अर्सा पहले तक मध्य प्रदेश सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि प्रदेश के किसान आजिज आकर आत्महत्या कर रहे हैं. जबकि इन आत्महत्याओं के बारे में सरकार को पक्की जानकारी थी. शासन और प्रशासन की संवेदनहीनता का चरम यह है सरकार की फर्जी छवि बनाए रखने के लिए किसानों की आत्महत्या को आधिकारिक तौर पर दर्ज ही नहीं किया जा रहा था. सरकार सोचती है कि किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ेगा तो सरकार की बदनामी होगी. आत्महत्या को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का रुख देखते हुए पुलिस प्रशासन किसानों की आत्महत्या को आत्महत्या में न दर्ज करके अन्य कारणों से हुई मौत दिखाता रहा और मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आत्महत्या से इन्कार करती रही. किसानों की आत्महत्या को लेकर जब भी कोई खबर आती तो सरकार की तरफ से उन खबरों का खंडन किया जाता रहा. कई मंत्री किसानों की मौत का मजाक उड़ाते रहे, यहां तक कि कई शर्मनाक बयान भी दिए गए. सरकार की तरफ से बताया जाता रहा कि किसानों की आत्महत्याएं (शेष पृष्ठ 2 पर)

आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार की व्यथा-कथा

उनकी पीड़ा नसों में तेज़ाब भर देती है, पर नेता को कुछ नहीं होता

नवीन चौहान

मध्य प्रदेश का चंबल का इलाका एक समय डकैतों के लिए जाना जाता था, चंबल का नाम लेते ही वहां के बीहड़ और डकैतों की कहानियां हर किसी के जेहन में उभर आती थीं. लेकिन आज चंबल के बीहड़ में गोलियों की आवाज नहीं, किसानों की आत्महत्या के कारण पीड़ित परिवारों से रुदन के स्वर सुनाई पड़ते हैं. अत्याचार के खिलाफ बंदूक उठाकर बीहड़ में कूदने वाला किसान आज विवश होकर आत्महत्या का रास्ता चुन रहा है. सरकारों की उपेक्षा और अमानवीयता के कारण अब किसानों का अपने पैरों पर उठ खड़ा हो पाना मुश्किल नजर आ रहा है. आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार की व्यथा-कथा सुनें तो उनकी पीड़ा आपकी नसों में तेजाब भर देती है, पर नेताओं-नौकरशाहों को कुछ नहीं होता.

उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के भिंड जिले की फूफ तहसील में आप प्रवेश करें तो तकरीबन सात ही किलो मीटर दूर है अहेंती गांव. यहां भदौरिया राजपूतों की बहुलता है. गांव में प्रवेश करते ही आपको सेना के कुछ शहीदों की समाधियां नजर आएंगी, पर गांव के अंदर जाएं तो किसानों की आत्महत्या की खौफनाक रुदालियां सुनाई देंगी. पिछले ही साल की तो बात है. 18 अप्रैल से पहले रामसिंह भदौरिया के घर पर सबकुछ ठीक ठाक चल रहा था. लेकिन 18 अप्रैल को उनके 35 वर्षीय किसान बेटे रक्षपाल ने फांसी लगा ली. ग्राम सेवक के पद से सेवानिवृत्त हुए रामसिंह के पास तकरीबन 30 बीघा खेती है. खेती उनके बेटे रक्षपाल सिंह संभालते थे. उस साल रक्षपाल ने खेत में गेहूं और सरसों की बोवाई की थी. उन्होंने अपनी जमीन के अलावा कुछ और लोगों की ज़मीन बटाई पर ली थी. इस वजह से खेती में उनकी लागत बहुत बढ़ गई थी. रक्षपाल को उस साल अच्छी पैदावार होने की उम्मीद थी, उसी की कमाई से रक्षपाल अपनी बेटी सुनीता की शादी करने की योजना बना रहे थे. लेकिन बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद कर दी और इसके साथ ही नष्ट कर दिया रक्षपाल का सपना. फसलें खराब हो गईं, बिटिया की शादी नहीं हो पाई, कर्ज का बोझ बढ़ गया और साहूकार का दबाव दम घोंटने लगा. घर में फांके की स्थिति हो गई. पिछले दो साल से खेती का यही हाल था. रक्षपाल को कोई उपाय नहीं सूझा. आखिरकार उसने फांसी लगा कर खुद को मुक्त कर लिया.

लेकिन उसका परिवार त्रासदियों में जकड़ गया. रक्षपाल के पिता बताते हैं कि उनके बेटे की सबसे ज्यादा चिंता कर्ज चुकाने की थी. रक्षपाल की फांसी से टंगी लाश उसकी बिटिया सुनीता ने सबसे पहले देखी जिसकी शादी की घर में गुनधुन चल रही थी. वह अपने पिता को चाय देने के लिए गई थी, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था. घर पर आज भी सन्नाटा पसरा हुआ है. बेटे की लाश को कंधा देने की बाप की पीड़ा, पिता रक्षपाल को तलाशती बेटी की आंखें, पत्नी की आंखों से थमती नहीं आंसुओं की धार आपको भी रुलाएगी और व्यवस्था के प्रति आक्रोश से भर देगी. (शेष पृष्ठ 3 पर)

मुनादी

संतोष भारतीय

यह विडंबना हिन्दुस्तान में ही हो सकती है कि पांच हजार से पच्चीस हजार रुपये कर्ज का बोझ जिंदगी से ज्यादा बड़ा बोझ बन जाये और कोई किसान आत्महत्या कर ले. पंजाब में सवा लाख का कर्ज जिसके सिर पर है, वह आत्महत्या कर रहा है. दूसरी तरफ बैंकों के करीब 18 लाख करोड़ रुपये औद्योगिक घरानों ने हज़म कर लिए हैं. वही बैंक जो किसी उद्योगपति के दरवाजे पर नोटिस नहीं चिपकाते, महज कुछ हजार रुपये कर्ज लेने वाले किसान के दरवाजे पर नोटिस चिपकाकर उसकी इज्जत और साख कौड़ियों के भाव बिखेर देते हैं. यह भेद किसानों में चेतना जाग्रत कर रहा है. सरकार इतनी बहरी है कि उसे किसानों की आत्महत्या से उपजी चीख नहीं सुनाई देती. संसद भी बहरी हो गई है जो किसानों का करुण क्रंदन नहीं सुन पा रही. संसद में किसानी का पेशा करने वाले 70 प्रतिशत से ज्यादा सांसद हैं. जिनका रिश्ता गांव से है वो भी किसानों की आत्महत्या की अनदेखी कर रहे हैं. कुछ सांसद तो यह कहते हैं कि किसानों ने आत्महत्या को फैशन बना लिया है. सांसदों द्वारा ऐसे बेरहम वक्तव्य दिया जाना देश के किसानों का अपमान है. क्या किसान संगठित होकर कॉरपोरेट के खिलाफ और कॉरपोरेट को बचाने वाली सरकार के खिलाफ संघर्ष का कभी ऐलान करेंगे! किसान संगठनों ने भी अलग-अलग चूल्हे बना लिए हैं. राजनीति में घुसने के लिए वे भी उन्हीं दलों का सहारा लेना चाहते हैं जो उनकी दुदर्शा के लिए जिम्मेदार हैं. किसान जब तक अपने आंसू पोंछने के लिए दूसरों के इंतजार में रहेंगे तब तक उनके आंसू खून बनकर बहते रहेंगे. जिस दिन देश का किसान आत्मविश्वास से भर कर अपने आंसू खुद पोंछने का फैसला कर लेगा उसी दिन से उसकी किस्मत और इस देश कि किस्मत बदलनी शुरू हो जायेगी. हमारा यह अंक संसद, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया के मुंह पर तमाचा है, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, पर उनके अंधेपन और बहरेपन को चुनौती अवश्य है. ■

मध्य प्रदेश में बन रहा किसानों की आत्महत्या का रिकॉर्ड

मृत्यु प्रदेश!

फोटो-प्रभात पाण्डेय

पृष्ठ 1 का शेष

पारिवारिक कलह, प्रेम प्रसंग, नशा या फिर पागलपन की वजह से हो रही हैं. लेकिन मीडिया, सामाजिक संस्थाएं और किसान संगठन किसान आत्महत्या के मुद्दे को लगातार उठाते रहे. शिवराज सिंह सरकार किसान आत्महत्या को ही नकारती रही तो पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का सवाल कहां से उठता. सरकार के नियोजन के बावजूद किसानों की आत्महत्या के मामले धीरे-धीरे उजागर होते चले गए और तमाम कतरब्यौंत के बीच आखिरकार प्रदेश सरकार को सच्चाई स्वीकार करनी ही पड़ी. मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में यह स्वीकार किया कि पिछले नौ महीनों के दरम्यान 897 किसानों ने आत्महत्या की और पिछले चार महीने में 342 किसानों ने फांसी लगा ली.

चौथी दुनिया का उद्देश्य किसानों की आत्महत्या के तकलीफदेह तथ्य को आंकड़ों में उलझाना नहीं है, बल्कि सुनियोजित तरीके से उलझा कर रखी गई उन वजहों को सामने लाना है जिन कारणों से किसान आत्महत्या कर रहे हैं. अगर शिवराज सिंह सरकार समय रहते सतर्क नहीं हुई तो इस साल मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या के सारे रिकार्ड टूट जाएंगे. यह जमीनी हकीकत भी है और सरकार के लिए चेतावनी भी. मध्य प्रदेश के नौकरशाहों की टोलियों ने भी प्रभावित गांवों का सर्वे करके शिवपाल सिंह सरकार को जमीनी रिपोर्ट दे रखी है, लेकिन यह रिपोर्ट सरकार की इतनी व्याधियां उजागर करती हैं कि सरकार ने उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसे दबा रखा है. वरिष्ठ नौकरशाहों की टीमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आदेश पर ही गांवों का दौरा करने गई थीं. 25 अक्टूबर, 2015 को ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अफसरों की टीमें अलग-अलग गांवों में गई थीं. ज्यादातर अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी उससे यह साबित हो गया कि किसानों ने नाकारा व्यवस्था से विवश होकर आत्महत्या की है. कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं का कोई लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है. इन रिपोर्टों से यह तथ्य आधिकारिक तौर पर सामने आया कि किसान कर्ज में डूब कर फांसी का रास्ता चुन रहे हैं. कई अधिकारियों ने यह माना और लिखा कि गांवों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है. खाद और बीज को लेकर किसान परेशान हैं और खेती में हुए नुकसान और ऊपर से कर्ज के बोझ की वजह से वे आत्महत्या कर रहे हैं. इन रिपोर्टों से सकते में आई सरकार ने चार महीने में 342 किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात स्वीकार की. हालांकि सामाजिक संस्थाएं कहती हैं कि सरकार इस संख्या को भी दबाकर बता रही है.

किसानों की आत्महत्या का मुख्य कारण उनसे बर्बर, अमानवीय और अतार्किक तरीके से कर्ज वसूला जाना है. कर्ज वसूल करने के जो मानक और मापदंड मध्य प्रदेश सरकार ने तय कर रखे हैं, उसे आप सुनेंगे तो आप निश्चित हो जाएंगे कि किसानों की आत्महत्याएं सरकार द्वारा नियोजित तरीके से उकसावा दिए जाने का परिणाम हैं. मध्य प्रदेश का किसान दो लाख, दस लाख और पंद्रह लाख तक के कर्जे में डूबा हुआ है. राज्य का ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां के किसान कर्ज के बोझ से लदे नहीं हैं. किसानों को राहत देने वाले किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए जो ऋण दिया जाता है वही किसानों के लिए सबसे अधिक घातक साबित हो रहा है. सरकार यह दावा करती है कि किसानों को शून्य प्रतिशत की दर पर ऋण दिया जाता है. लेकिन इस सरकारी योजना की जमीनी हकीकत विचित्र और अमानवीय है. एक बार जो किसान इस सरकारी ऋण की योजना में फंस गया उसे जिंदगी भर के लिए ऋण के दलदल में फंसा लिया जाता है. दरअसल, इस ऋण योजना की शर्त यह है कि किसानों को हर साल पूरा ऋण लौटाना अनिवार्य होता है. ऋण लौटाने की आखिरी तारीख 15 मार्च निर्धारित है. अगर कोई किसान 15 मार्च तक पैसे जमा नहीं करेगा तो वह डिफॉल्टर हो जाएगा. इस तारीख का निर्धारण ही किसानों के खिलाफ षडयंत्र का सबूत है. मार्च वित्त-वर्ष का आखिरी महीना सरकार और बैंक के लिए हो सकता है, लेकिन किसानों की मंडी 15 अप्रैल को खुलती है, जहां वह अपनी फसल बेच कर ऋण की अदायगी कर सके. किसान होने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह या खुद को किसानों की हितैषी कहने वाली भाजपा के झंडाबरदारों को इतना भी नहीं पता कि 15 मार्च तक तो किसानों की फसलें खेतों में ही खड़ी रहती हैं. मार्च के आखिरी सप्ताह में कटाई शुरू होती है. क्या सरकार को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि जब सरकारी मंडी 15 अप्रैल को खुलती ही है तो किसान अपने ऋण कैसे वापस कर पाएगा? किसान 15 अप्रैल के बाद मंडी खुलने पर अपनी उपज बेचता है. पैसे मिलने में भी कम से कम 15 दिन का समय लग जाता है. सरकार की धूर्तता देखिए कि वह मई के महीने में किसानों को पैसे देती है लेकिन ऋण वापस करने की आखिरी तारीख 15 मार्च तय कर देती है. साफ है कि यह योजना बनाई ही ऐसी गई है कि किसान डिफॉल्टर हो जाए. 15 मार्च की निर्धारित तारीख के बाद किसानों को 16 फीसदी की दर से इंट्रेस्ट देना होता है. इसके अलावा ऋण लेने के साथ ही 3 फीसदी बीमा राशि के रूप में रख लिया जाता है. इसके अलावा किसानों को ऋण लेने के लिए कई बैंकों और सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाकर क्लियरेंस लेना होता है, उसमें भी पैसे खर्च होते हैं. कुल मिला कर किसानों को शून्य फीसदी इंट्रेस्ट पर मिलना वाला ऋण एक छलावा है, जिसमें उन्हें 22-24 फीसदी की दर से ऋण का भुगतान करना पड़ता है. सरकार यह कतई नहीं कह सकती कि किसानों की इस समस्या से वह वाकिफ नहीं है. भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कहते हैं कि वो सरकार को मीडिया के माध्यम से कई बार यह बता चुके हैं कि जीरो फीसदी ब्याज वाली ऋण योजना छलावा है. किसानों के खिलाफ एक षडयंत्र है, जिसकी चपेट में आकर किसान तबाह हो जाता है.

अब सरकारी तिकड़म को तफसील से देखिए. जो किसान इस ऋण योजना के जरिए पैसे लेने हैं उनकी गर्दन पर 15 मार्च की तलवार लटकी होती है. किसानों को मदद देने के नाम पर सरकार खुद ही सूद-चूसने वाले महाजन की भूमिका में आ जाती है. किसानों के पास 15 मार्च तक ऋण लौटाने का पैसा नहीं होता तो बैंक उस किसान को फिर से लोन दे

किसानों की आत्महत्या का मुख्य कारण उनसे बर्बर, अमानवीय और अतार्किक तरीके से कर्ज वसूला जाना है. सरकार किसानों से खुद सूदखोरों की तरह कर्ज वसूल रही है.

देती है. बैंक अगले ही दिन इस नए लोन से मिले पैसे को जमा करा लेता है. इस तरह कागज पर किसान पिछले साल का कर्ज लौटा देता है और 16 फीसदी ब्याज देने से बच भी जाता है. लेकिन बैंक यहां खतरनाक खेल यह कर देता है कि किसानों को जो नया लोन मिलता है उसमें वह पिछले लोन का 10 फीसदी जोड़ कर देता है. अगर किसी किसान ने एक लाख रुपये का लोन लिया था तो बैंक उसे अगले साल एक लाख 10 हजार रुपये का लोन दे देता है. लिहाजा, किसान हर साल 10 फीसदी के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा कर्ज में दबा चला जा रहा है. किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर जीरो फीसदी ब्याज के नाम पर जो मदद दी जा रही है वो दरअसल किसानों को हर साल पहले से ज्यादा कर्जदार बना रही है. साल दर साल किसान पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और इससे निजात का रास्ता नहीं पाकर वह आत्महत्या कर रहा है.

यह तो हुई किसानों की आत्महत्या की सबसे प्राथमिक वजह. इसके अलावा सरकारी लापरवाहियों के कारण अन्य मुश्किलें खड़ी होकर किसानों की मौत की वजह का घेरा बनाती हैं. मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में आप देखें तो किसान शासन-जनित मुश्किलों के घेरे में घिरे दिखेंगे. किसानों की समस्याओं के प्रति सरकारी संवेदनहीनता की वजह से मध्य प्रदेश किसानों के लिए मृत्यु प्रदेश में तब्दील हो रहा है. दूसरी तरफ प्रकृति भी किसानों को मार रही है. पिछले तीन चार साल से लगातार कभी सूखा, कभी ओला तो कभी अतिवर्षा की वजह से किसानों की फसल बर्बाद होती रही है. खासकर पिछले दो साल में फसल अच्छी नहीं हुई है. पैदा हुआ गेहूं खाने लायक नहीं. सोयाबीन की फसल तो बिलकुल ही बर्बाद हो गई. किसान की लागत में तो लगातार वृद्धि हो रही है पर उपज कम होती जा रही है. ज्यादातर किसान कर्ज लेकर खेती कर रहे हैं. पिछले दो साल से किसानों को लगातार भारी घाटा हुआ है. खेती से प्राप्त आय से किसान अपने घर को चलाने में असमर्थ होते जा रहे हैं. ऐसे में किसान अपने पारिवारिक दायित्व यानि शादी विवाह, बच्चों की पढ़ाई और पर्व-त्यौहार के लिए पैसे कहां से लाएगा. अपनी प्रतिष्ठा समाज में कैसे बचा पाएगा. किसानों की आर्थिक स्थिति ने किसानों की मानसिक स्थिति को तनावग्रस्त कर दिया है. किसान वर्तमान और भविष्य को लेकर उदासीन हैं. यही वजह है कि किसानों ने भारी संख्या में आत्महत्या की. अगर इस साल भी यही हाल रहा तो किसान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा. जो वर्तमान स्थिति है. इस साल मौसम का जो हाल है. फिलहाल खेतों में फसल की जो हालत है और राज्य सरकार का जो गैरजिम्मेदाराना रवैया है उसमें बड़ी तादाद में किसानों की आत्महत्या की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता.

मध्य प्रदेश के अधिकतर ग्रामीण इलाकों में फरवरी और मार्च के महीने में ही मई-जून की तरह पानी की कमी है. हर तरफ हाहाकार है. सरकार चैन की नींद सो रही है. प्रशासन लापरवाह और संवेदनहीन है. सरकार मध्य प्रदेश के किसानों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले अवार्ड को प्रचारित करने में लगी है. झूठ और फरेब से किसानों को मौखिक रूप से खुशहाल साबित करने में शिवराज सिंह जुटे हैं. जबकि खेतों में किसान निराश और परेशान हैं. खेतों को देख कर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को रोना आ जाए. इस बार गेहूं, चना, मसूर, धनिया जैसी कई फसलों की उपज ठीक नहीं है. पानी की कमी तो सब जगह है, लेकिन सबसे बुरा हाल बुंदेलखंड और चंबल इलाके का है. सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है और भू-जल स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है. सिंचाई की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को सिंचाई के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है. किसान किसी इलाके में सौ रुपये तो किसी इलाके में दो सौ रुपये प्रतिघंटे के हिसाब से पानी खरीदने को मजबूर है. कुछ इलाकों में तो पानी का स्तर इतना नीचे जा चुका है कि कुएं और पंप बेकार हो गए हैं. मई और जून में क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. अगर बारिश नहीं हुई तो लोगों के लिए पीने का पानी भी दुर्लभ हो जाएगा. सिंचाई के लिए पानी कहां से आएगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है. मध्यप्रदेश के दरवाजे पर इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी है लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पूरे राज्य में कृषि कर्मण अवार्ड की होर्डिंगें लगाकर अपनी पीठ खुद थपथपा रही है.

किसानों की आत्महत्या की एक और वजह यहां व्याप्त भ्रष्टाचार है. हर काम के लिए किसानों को अधिकारी ठग रहे हैं. यहां किसानों को राहत पहुंचाने वाली नीतियों की भी कमी है. मध्य प्रदेश में खाद पर वैट लगता है. कृषि यंत्रों पर टैक्स लगता है. यहां ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन में दूसरे राज्यों से ज्यादा टैक्स लगता है. मध्य प्रदेश में मंडी का शुल्क भी ज्यादा है. किसान हर तरफ से लूटा जा रहा है. इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश नकली खाद और नकली बीज का भी अड्डा बना हुआ है. नकली कीटनाशक यहां बिकता है. भोले-भाले किसानों को कैसे धोखा देकर लूटा जा सकता है वह सारा दृश्य मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है. किसान सरकारी बीज बोता है लेकिन उसमें फसल नहीं होती. अब बीज ही नकली निकल जाए तो पैदावार कैसे होगी. किसान यूरिया खरीद कर लाता है. वह भी नकली निकलता है. किसान इस तरह की शिकायतें मध्य प्रदेश के हर इलाके में करते मिलेंगे. पता चला कि मध्य प्रदेश में खाद की जांच करने की एक ही लैबोरेटरी है और वह जबलपुर में है, जो कि 1965 में बनी थी. यह लैब नकली खाद की बिक्री रोकने में कारगर साबित नहीं हुई है. साफ है कि मध्य प्रदेश में नकली बीज, नकली खाद और नकली कीटनाशक का कारोबार सरकारी संरक्षण में बहुत ही संगठित ढंग से चल रहा है. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सरकार और अधिकारियों को इसके बारे में पता न हो. दोषी लोगों पर आज तक कोई कार्रवाई न होना यही साबित करता है. हैरानी यह है कि राज्य की विपक्षी पार्टियां भी किसानों की तबाही के मसले पर कोई आवाज नहीं उठा रहीं. किसान संगठन भी इन मुद्दों पर मीडिया में बयानबाजी कर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं. किसानों के साथ खड़े होकर उन्हें लामबंद करने और जुझारू आंदोलन करने की कोई पहल नहीं हो रही. मुसीबतों से घिरा किसान व्यक्ति के तौर पर सत्ता-व्यवस्था से नहीं लड़ सकता. किसान इतना पढ़े लिखे भी नहीं कि वे प्रशासन तक पहुंच कर नकली बीज, नकली खाद और नकली कीटनाशक की शिकायत दर्ज करा सकें. कुछ पहुंचे भी तो उल्टे पुलिस के हाथों प्रताड़ित हुए. यह अजीब विडंबना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की होर्डिंग प्रदेश के हर शहर और चौराहों पर लगी है जिसमें वे मुस्कुराते हुए अन्नदाता को धन्यवाद देते नजर आते हैं, यह किसानों के साथ क्रूर मजाक ही तो है. इन होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त कृषि कर्मण अवार्ड की गाथा टंगी है. इस गाथा में है कि मध्य प्रदेश अनाज पैदा करने में देश का सबसे अव्वल राज्य बन गया है. इस वजह से पिछले चार साल से मध्य प्रदेश को लगातार यह अवार्ड मिल रहा है.

अनाज उत्पादन में मध्य प्रदेश के अव्वल आने का मसला भी भीषण घपला और धोखाधड़ी का परिणाम है. सवाल है कि पिछले तीन साल से जब मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा है और हर जगह फसलें नष्ट हुई हैं तो राज्य की पैदावार कैसे बढ़ गई. यह पूरा मामला नियोजित धोखाधड़ी है. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों से यह तय होता है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा उपज हुई है. घपला यह किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से सटे दूसरे राज्यों से अनाज को तस्करी कर मध्य प्रदेश की मंडियों में एफसीआई को बेचा जाता है. मध्य प्रदेश सरकार गेहूं में एफसीआई की दर से सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देती है. इस वजह से दूसरे राज्यों का गेहूं मध्य प्रदेश की मंडियों में आकर बिकता है. भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा कहते हैं कि राशन की दुकानों का अनाज भी गरीबों तक नहीं पहुंच कर मंडियों में वापस पहुंच जा रहा है. गरीबों के पास अनाज पहुंचने के बजाय एफसीआई के गोदामों तक पहुंच रहा है. इससे पैदावार का आंकड़ा बढ़ जाता है. शिवकुमार शर्मा का दावा है कि उन्होंने कई बार इस फर्जीवाड़े को पकड़वाया भी है और सरकार से आरटीआई के तहत पिछले साल गेहूं की पैदावार की जानकारी मांगी तो सरकार से दो अलग-अलग विरोधाभासी जवाब मिले.

सरकारी लापरवाही का दूसरा परिदृश्य देखें. फसल नष्ट होने के बाद भी किसानों के लिए सरकारी राहत की कोई व्यवस्था नहीं है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के लिए बीमा की तो घोषणाएं कर रही है लेकिन इसका लाभ किसानों को नहीं मिलने वाला. प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने के बाद किसानों को कम से कम इतना जरूर मिलना चाहिए जिससे उसकी लागत निकल सके. जबकि वर्तमान व्यवस्था ही गलत है. प्राकृतिक आपदा आने के तीन महीने बाद तो सरकार सर्वे करा पाती है. सरकार को कौन समझाए कि तीन महीने तक किसान नहीं रुक सकता है, उसे अगली फसल की तैयारी शुरू करनी होती है. अधिकारी दफ्तर में बैठकर ही मूल्यांकन कर रहे हैं और किसान जमीन पर आत्महत्या कर रहे हैं. ■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 04
28 मार्च-03 अप्रैल 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार की व्यथा-कथा

उनकी पीड़ा नसों में तेज़ाब...

पृष्ठ 1 का शेष

रक्षपाल के पिता राम सिंह कहते हैं कि पिछले दो साल से कुदरत का कहर टूट रहा है, लेकिन सरकार की तरफ़ से कोई मुआवज़ा नहीं मिला. जिसे मिला भी, तो बेहद कम. खाद-बीज सब कुछ किसान सोसायटी से लेता है. मेरे बेटे ने खेती में हुए नुक़सान की वजह से आत्महत्या की, लेकिन कोई सुनता नहीं है. सरकार और नेताओं को किसानों की चिंता नहीं है. प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष एवं अटेर के विधायक सत्यदेव कटारे बेटे की मौत के बाद गांव तो ज़रूर आए, लेकिन उन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया. सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया. तहसीलदार, एसडीएम या किसी भी अधिकारी ने कोई खोज ख़बर नहीं ली. मीडिया वालों ने भी सहयोग नहीं किया, वे नेताओं के साथ तो आए, लेकिन फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा.

गांव वाले स्पष्ट कहते हैं कि जैसे नेता हैं वैसे ही नौकरशाह और वैसे ही मीडिया वाले हैं. किसानों की तकलीफ से किसी का कोई लेना-देना नहीं है. सबके अपने-अपने धंधे हैं और अपनी-अपनी स्वार्थपरक प्राथमिकताएं हैं. किसानों की आत्महत्या पर अगर कारगर विरोध होता तो नौबत ही नहीं आती. प्राकृतिक आपदाओं में किसानों को मिलने वाला मुआवजा नेता, नौकरशाह और दलाल मिल कर खा नहीं जाते. बैंक को औजार बना कर केवल मध्य प्रदेश ही क्या पूरे देशभर के किसानों को लूटा नहीं जा रहा होता. और मजबूर किसानों को आत्महत्या के लिए विवश नहीं होना पड़ता. ■

रक्षपाल सिंह (इनसेट) के पिता राम सिंह और बेटी सुनीता. सभी फोटो-प्रभात पाण्डेय

इस तरह उजड़ गया सुंदर संसार...

तबाह किसान परिवारों की तो जैसे कतार लगी है. पूरे क्षेत्र के माहौल में ही पीड़ा पसरी हुई महसूस होती है. भिंड जिले के चरी कनावर गांव के किसान मुन्ना सिंह भदौरिया का घर भी अतिवृष्टि और ओलावृष्टि की वजह से उजड़ गया. मुन्ना सिंह भदौरिया के बड़े बेटे 26 वर्षीय सुंदर सिंह ने अपने खेत के पास ही पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली. रात में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद सुबह फसल की हालत देखने गए सुंदर बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहीं पर आत्महत्या कर ली. परिवार में सुंदर के बूढ़े मां-बाप, उसकी पत्नी, तीन बच्चे और छोटा भाई हैं. सुंदर के देहांत के बाद अब परिवार की सारी जिम्मेदारी छोटे भाई अनिल के कंधों पर आ गई है. उनके पास कुल खेती ढाई बीघा की है, ऐसे में परिवार का खर्च चलाकर कर्ज चुकाना संभव नहीं है. परिवार को उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है. सुंदर सिंह के ताऊ राजा सिंह ने कहा कि सरकारों को किसानों की कोई चिंता नहीं है. शिवराज सिंह की सारी घोषणाएं खोखली हैं. मेरे भतीजे के घर में खाने को नहीं है अब पता नहीं आगे क्या होगा. उसका परिवार कैसे चलेगा. चार साल से इस क्षेत्र में बारिश नहीं होने की वजह से फसल नहीं हो पा रही थी. ऐसे में कई लोग रोजगार की तलाश में दूसरे शहर चले गए. काम की तलाश में गांव से बाहर गए लोगों की जमीन भी खाली पड़ी थी. चार साल बाद बारिश हुई तो खेती के हालात बेहतर हुए. आठवीं पास सुंदर ने चार साल की बदहाली दूर करने के लिए बलकट (किराए) पर पांच हजार रुपये प्रति बीघा की दर से 40 बीघा ज़मीन ली थी. इसके एवज में उन्हें लोगों को दो लाख रुपये देने थे. उसे खुद पर विश्वास था. सुंदर ने खेत में गेहूं और सरसों की बोवनी की. तीन-चार महीने तक फसल को खाद-पानी-दवा देकर लहलहाता देख वह खुश था. लेकिन कुदरत का कहर फिर किसानों के सिर बरपा. अतिवृष्टि और ओलावृष्टि ने देखते देखते लहलहाती फसलों को बर्बाद कर दिया. इसी बर्बादी ने सुंदर की बलि ले ली. सुंदर के ताऊ यह भी बताते है कि भिंड के इस क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है, नहरें न होने की वजह से फसलों में पानी लगाने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं. खेतों में पानी देने के लिए निजि नलकूप मालिकों को 100 रुपये प्रतिघंटा के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं. हर फसल में दो से तीन बार पानी लगाना पड़ता है. इसके अलावा किसान को ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई के लिए 150 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से पैसे देने होते हैं. एक बीघा सरसों की फसल में एक बोरी डीएपी और एक बोरी यूरिया डालनी पड़ती है. जबकि गेहूं में एक बोरी डीएपी और दो बोरी यूरिया डालनी पड़ती है. एक बोरी यूरिया की सरकारी कीमत 305 रुपये और डीएपी की कीमत 1257 रुपये है. लेकिन यह भी सही समय और सही दाम में किसान को उपलब्ध हो जाए तो गनीमत है. नहीं तो खाद की कालाबाजारी भी किसान की जेब काटने के लिए काफी है. किसान अपनी खेत में खड़ी फसल को अधर में भी नहीं छोड़ सकता. दिन-ब-दिन खेती की लागत बढ़ती जा रही है. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेत में खड़ी फसल के खराब होने पर किसानों पर क्या गुजरती है.

मरहूम सुंदर सिंह के ताऊ राजाराम (हाथ में भतीजे की फोटो लिए)

सुंदर की आत्महत्या की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई थी. पूर्व सासंद गोविंद सिंह ने 10 हजार रुपये परिवार को सहायता स्वरूप दिए. जबकि वर्तमान विधायक और मप्र के नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे 20 हजार रुपये देने का आश्वासन देकर चले गए. भिंड के तत्कालीन कलेक्टर मधुकर आग्नेय के नेतृत्व में एक टीम मौके पर पहुंची थी. किसान की आत्महत्या पर शोक और संवेदना जताने के बजाय कलेक्टर ने कहा कि इतना बड़ा मकान बना है तो कमी किस बात की. कलेक्टर ने पीड़ित परिवार की सहायता करने की कोई बात ही नहीं की. सुंदर सिंह का मकान पुश्तैनी है. पिछली तीन पीढ़ियों से उनका परिवार इसी मकान में रह रहा है. आत्महत्या से क्रोधित ग्रामीणों ने कलेक्टर का विरोध किया और कहा कि आप भ्रष्ट हैं आपको किसान का दर्द समझ में नहीं आता. ग्रामीणों की नाराजगी देखकर कलेक्टर वहां से खिसक लिए. फिर कभी सुंदर के परिवार की ओर मुड़कर भी नहीं देखा. ■

फांसी चढ़ गई पांच-पांच बेटियों की अभिलाषा

अभिलाख सिंह यादव की पत्नी गुड्डी देवी और बच्चे

भिंड जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किमी दूर स्थित उमरी गांव निवासी अभिलाख सिंह यादव ने फसल बर्बाद होने के कारण आत्महत्या कर ली. 35 वर्षीय अभिलाख सिंह के पास खुद की तीन बीघा जमीन थी. उन्होंने 10 बीघा जमीन आठ हजार रुपये की दर से बलकट पर ली थी. खेती करने के लिए उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक ट्रैक्टर भी फाइनेंस कराया था. अभिलाख यादव के पांच बेटियां व एक बेटा है. अभिलाख अपने भाइयों से अलग एक छोटे से मकान में गुजर बसर कर रहा था. आठ सदस्यीय परिवार में पांच बेटियां ज्योति (18), मोहिनी (16), जूली (14), रोशनी (12), चांदनी (7) वर्ष के अलावा एक डेढ साल का बेटा और पत्नी गुड्डी देवी हैं. बेमौसम बरसात के कारण पिछले साल भी फसल खराब हो गई थी. इस साल भी बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि की वजह से खेत में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल खराब हो गई, एक दाना खेत से घर तक नहीं पहुंचा. अपने सुसाइड नोट में अभिलाख ने लिखा कि हम अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करेंगे. हम यह सदमा सहन नहीं कर पा रहे हैं. हम अपनी खेती की हालत देखकर अपने खेत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहे हैं. हे, भगवान हमारे बच्चों को देखें.

अभिलाख की पत्नी गुड्डी देवी (32) बताती हैं कि ओलावृष्टि और बरसात के कारण फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी. लगातार दो साल से फसल बर्बाद होने के कारण लोगों का कर्जा भी था. उन्हें बड़ी होती बच्चियों की शादी की चिंता भी सता रही थी. बलकट पर भी जमीन ली लेकिन उसमें भी घाटा हो गया, जो कुछ जमापूंजी थी बलकट की खेती में चली गई. इसलिए मेरे पति काफी परेशान थे. उनके देहांत के बाद प्रशासन का कोई आदमी हमारी सुध लेने नहीं आया. इसके आलावा उन्होंने जो बीज सोसायटी से लिया था, वह बीज भी नहीं जमा. सहकारी बैंक और साहूकारों से कर्ज लिया था. अभिलाख के पिता का कहना है कि बेटे के नहीं रहने के बाद उनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई है. अब बुढ़ापे में उनसे खेत में काम नहीं होता. ट्रैक्टर का कर्ज भी बाकी है, किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज है. साहूकारों का कर्ज है. यह सब कैसे चुकता होगा. इसके बाद बेटियों की शादी कैसे होगी. बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी समझ में नहीं आता. इनका तो अब भगवान ही मालिक है. सरकार को हमारा कर्ज माफ कर देना चाहिए. तभी हम कुछ कर सकेंगे. ■

(शेष पृष्ठ 4 पर)

आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार की व्यथा-कथा

उनकी पीड़ा नसों में तेज़ाब...

पृष्ठ 3 का शेष

लीलाधर की दर्दनाक जीवन लीला

लीलाधर पटेल की पत्नी दीपरानी और बेटी पूजा

दमोह ज़िले के सीतानगर निवासी किसान लीलाधर पिछले तीन साल से खेती न हो पाने की वजह से चिंतित रहते थे. उनके पास छह एकड़ भूमि है. उनकी पत्नी दीपरानी बताती हैं, खेती-बाड़ी में लगातार घाटा होने की वजह से उनकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई. बेटी पूजा (20) शादी के लायक हो गई थी. शादी के लिए लड़का देखने जाते, पर मांग ज़्यादा होने की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी. 20 नवंबर 2015 को वह खेत में सोयाबीन काटने गए. वहां एक भी दाना नहीं निकला, सब भूसा था. अचानक खेत से घर की ओर निकले. शाम को घर पर कोई नहीं था, उन्हें घर पर पूजा की एक चुन्नी दिखाई दी, उन्होंने उसे रोशनदान से बांधा और फांसी लगा ली. पुलिस को सूचना दी गई. प्रशासन ने कहा कि वह पागल हो गए थे, इसलिए फांसी लगा ली. इस तरह कोई सरकारी मुआवज़ा भी नहीं दिया गया. दीपरानी कहती हैं, अब मुझे घर की सारी ज़िम्मेदारी संभालनी पड़ रही है. किसी तरह का मुआवज़ा सरकार से नहीं मिला और न कोई दूसरी राहत. स्टेट बैंक का अभी भी 50 हज़ार रुपये का कर्ज है, जिसे इस साल 15 मार्च तक जमा करना है. इसके अलावा 50 हज़ार रुपये साहूकार के देने हैं. उन्होंने बताया कि अब वह खेती देखती हैं. बेटी की शादी और बेटे की पढ़ाई का ज़िम्मा उन्हीं के सिर पर आ गया है. बेटा दमोह में पढ़ रहा है. आठ-नौ बीघा खेती बटाई पर ली है, जिसमें गेहूं और मसूर बोई है. फसल अभी कटकर आई नहीं है, उसी से पहले कर्ज पटाने की चिंता है. कर्ज चुकाएं या पेट भरें, समझ में नहीं आता. किसान की ज़िंदगी में तो भुगतना ही लिखा है, कुछ नहीं रखा है खेती-बाड़ी में. बेटी पूजा से पिता के बारे में पूछते ही उसकी आंखें भर आईं. पूजा को अफ़सोस है कि उसके पिता अब उसे डोली में बैठता नहीं देख पाएंगे. ■

पूर्व सरपंच भी फांसी लगाने पर विवश हुआ

पूर्व सरपंच नरेंद्र सिंह की पत्नी रेखा और मां कुंती देवी

चरी कनावर गांव के पूर्व सरपंच नरेंद्र सिंह ने भी उसी दरम्यान फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. चार साल से फसल न होने के कारण वह बेहद परेशान थे. उनकी पत्नी रेखा बताती हैं, खेती के लिए कर्ज चुकाने की चिंता के चलते उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. दस साल पहले नरेंद्र गांव के सरपंच बने थे. सरपंच के रूप में उनका कार्यकाल अच्छा था. उन्होंने एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल कर रखी थी. उनके पास तीन बीघा ज़मीन है. उन्होंने 10 बीघा ज़मीन बलकट पर ली थी, ताकि घर का खर्च चल सके और बच्चों की पढ़ाई में परेशानी न हो. परिवार में पत्नी रेखा, तीन बेटे, एक बेटी और मां कुंती देवी सहित छह सदस्य थे. पति की मौत के बाद रेखा की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. जिस दिन यह हादसा हुआ, वह अपने मायके में थीं. पिछले साल चैत मास की पूर्णमासी के दिन नरेंद्र खेत पर गए और वहीं उन्होंने मौत को गले लगा लिया. पास के दरुआ गांव से बकरी चराने आए बच्चों ने शाम को उन्हें बबूल के पेड़ पर लटका देखा. उनके पास से हिसाब-किताब की एक पर्ची मिली थी, जो प्रमाण है कि कर्ज के चक्रव्यूह ने उन्हें मौत चुनने पर मजबूर कर दिया. ■

क्रेडिट कार्ड के कर्ज ने घनश्याम की जान ले ली

मरहूम घनश्याम पटेल

सीहोर के आष्टा विकास खंड के सेंवदा गांव निवासी किसान घनश्याम पटेल ने उपज न होने की वजह से आत्महत्या कर ली. चार-पांच साल से खेती में कुछ नहीं हुआ था. किसान क्रेडिट कार्ड से उन्होंने कर्ज लिया था. खेती-बाड़ी पटरी पर नहीं थी. उन्होंने भूमि विकास बैंक से भी डेयरी के लिए कर्ज लिया और गाय खरीद लाए. लेकिन, फसल खराब होने की वजह से गायों के लिए भूसे का इंतजाम नहीं हो पाया. इस दौरान कुछ गायों की मौत भी हो गई. वह तीन महीने पहले तक बात-बात में आत्महत्या करने का जिक्र करते थे, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया. एक दिन सचमुच उन्होंने खेत में आम के पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली.

घनश्याम के भाई मुकेश पटेल बताते हैं, इस साल सात एकड़ ज़मीन में 4.2 क्विंटल सोयाबीन हुआ. जो मुआवज़ा मिला, वह बेहद कम है. हमारे यहां पानी की समस्या है. जिसके पास पानी की व्यवस्था है और जो किसान को पानी देता है, उसे पानी के बदले उपज का एक तिहाई हिस्सा देना होता है. इलाके की सिर्फ़ 25 प्रतिशत ज़मीन सिंचित है, बाकी 75 प्रतिशत भगवान भरोसे है. एक एकड़ में 22 क्विंटल सोयाबीन होना चाहिए, लेकिन आठ-नौ क्विंटल ही निकल रहा है. किसान की ज़मीन जिस दिन नीलाम होगी, उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी. हमने 33 एकड़ में दो लाख रुपये की लागत से सोयाबीन की खेती की थी, लेकिन कुछ भी पैदा नहीं हुआ. सरकार ने मुझे 22,583 रुपये मुआवज़े के रूप में दिए, जो मेरी कुल लागत का तक़रीबन दस प्रतिशत मात्र है. ■

बेटे की मौत से खो गईं कम्मोद की उम्मीदें

सीहोर के ही एक गांव चितौड़िया लाखा में पांच साल पहले कम्मोद सिंह के किसान पुत्र दयाराम सिंह मालवीय ने अपने खेत के कुएं में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. उनके पास लगभग चार एकड़ ज़मीन थी. खेती के साथ वह मज़दूरी भी करते थे. दयाराम ने अपने खेत में शरबती गेहूं लगाया था. पानी की कमी के चलते फसल खराब हो गई. इस वजह से वह काफी परेशान थे. इससे पहले सोयाबीन की फसल भी खराब हो गई थी. सोयाबीन की खेती में लगी मज़दूरी भी नहीं निकल पाई थी. सोयाबीन की खेती में दो तिहाई लागत होती है और एक तिहाई बचत, लेकिन मौसम की मार के चलते किसान फसल की लागत भी नहीं निकाल पा रहा है. दयाराम के भाई कृपाल सिंह बताते हैं कि 1300 रुपये में एक बैग डीएपी और 250 रुपये में सुपर फॉस्फेट मिलती है. एक एकड़ में एक बोरी डीएपी और तीन बोरी सुपर फॉस्फेट लग जाती है, कीटनाशक का खर्च अलग. सोयाबीन की सेवा बहुत करनी पड़ती है. हाथ से ही खरपतवार निकालनी होती है. मज़दूर लगाने पड़ते हैं. लेकिन, पानी की कमी या ज़्यादा बारिश के चलते खेती में लगातार नुक़सान हो रहा है. ऐसे में किसान आत्महत्या न करे, तो क्या करे. ■

दयाराम के पिता कम्मोद सिंह मालवीय. दयाराम की फोटो लिए उसकी विधवा (इनसेट)

(शेष पृष्ठ 5 पर)

आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार की व्यथा-कथा

उनकी पीड़ा नसों में तेजाब...

पृष्ठ 4 का शेष

किसान की विधवा का दर्द

रणबीर सिंह की पत्नी और बेटा राहुल

आत्महत्या कर चुके किसान की विधवा जब यह कहती हैं कि किसान होना तो पाप हो गया है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. होशंगाबाद ज़िले की पिपरिया तहसील के कुड़ारी गांव निवासी 40 वर्षीय किसान रणबीर सिंह ने अप्रैल 2015 में बेटी की शादी की थी. उसके बाद से वह कर्ज में थे. किसान क्रेडिट कार्ड पर 1.5 लाख रुपये का कर्ज था. उनके पास छह एकड़ ज़मीन है, जिसमें उन्होंने धान और मूंग लगाई थी. एक बार फसल खराब हो गई, तो उन्होंने दोबारा लगाई, लेकिन वह भी खराब हो गई. उनकी पत्नी बताती हैं कि एक एकड़ में मूंग के 12-14 किलो बीज लगते हैं. पहली बार 70 किलो बीज लगे और दोबारा भी उतने ही. इससे परेशान होकर उनके पति ने सल्फास खा लिया. इलाज के लिए उन्हें होशंगाबाद ले जाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई.

वह कहती हैं, ज़रूर पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, जो इस तरह की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है. भगवान हमें कुछ भी बनाना, पर अगले जन्म में किसान मत बनाना. आठ अक्टूबर, 2015 को रणबीर की मौत के बाद उनके 17 वर्षीय बेटे राहुल रघुवंशी ने पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के निर्वहन के लिए नौवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी. छोटा भाई अभी पढ़ रहा है. विडंबना यह है कि परिवार के पास ऐसा कोई कागज नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो कि रणबीर सिंह की मौत ज़हर खाने की वजह से हुई. पुलिस ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार को उपलब्ध नहीं कराई. वह कहती हैं कि अब बेटे को पढ़ाई छोड़कर खेती करनी पड़ रही है. पढ़-लिख जाता तो इंसान बन जाता, लेकिन अब उसे भी ज़िंदगी भर किसानी की मार सहनी पड़ेगी. सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की, कोई सरकारी कर्मचारी हमारी ख़ैर-ख़बर लेने तक नहीं आया. ■

फसल खराब हो गई तो खुद को ही फूंक डाला

पथरिया नगर (वार्ड नंबर 15) निवासी ललन यादव के पास 15 एकड़ ज़मीन है. उन्होंने अपने खेतों में सोयाबीन बोया था. सोयाबीन इतना खराब था कि उन्होंने खेत से काटा ही नहीं. खेती के लिए उन्होंने साहूकारों से क़रीब चार लाख रुपये कर्ज लिया था. किसान क्रेडिट कार्ड से कभी कर्ज नहीं लिया. सात क्विंटल बीज सोसायटी से लेकर लगाए थे, 15 बोरी डीएपी डाली, 10 हज़ार रुपये के कीटनाशक डाले, लेकिन पानी न होने की वजह से फसल नहीं हो पा रही थी. सारा परिवार खेती पर निर्भर है, ललन के तीन बच्चे हैं, बबलू (35), पप्पू (30) और विनीत (28). दो बच्चों की शादी हो चुकी है. तीन साल से फसल खराब होने की वजह से वह छोटे बेटे की शादी नहीं कर पा रहे थे. ललन के भाई रमन बताते हैं कि जिस दिन उन्होंने आत्महत्या की, उस दिन उन्होंने घर से खेत पर जाने की बात कही. खेत पर एक कमरा बनाया था, वह रात में वहीं रहते थे. खेत जाने के लिए घर से शक्कर, चायपत्ती, दूध और बीड़ी ले गए थे. वहां आग और डिबरी जलाने के लिए मिट्टी का तेल भी लिया. 10 मिनट बाद उनके भाई को भी खेत में जाना था. वह दस मिनट पहले निकले थे. जब उनके भाई खेत में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि ललन ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी. पत्नी जनक दुलारी कहती हैं कि उस दिन भी उनके व्यवहार से कुछ अलग नहीं लग रहा था. वह रोज की तरह व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा था, पता नहीं चला. इस क्षेत्र में पानी की बेहद कमी है. जो कुएं और नलकूप हैं, वे सब सूख गए हैं. इस साल भी वर्षा नहीं हुई, इसलिए इस बार भी खेती कमज़ोर है. खेतों में पानी ही नहीं लग पाया. ऐसे में किसान जाएं, तो कहां जाएं. ललन यादव की पत्नी कहती हैं कि सरकार ने कोई मदद नहीं की. घटना के बाद एसडीएम आए थे, पूछताछ करके चले गए. उन्होंने दो बोरी बीज ब्लॉक से भेजे, उसके बाद किसी ने कोई मदद नहीं की. हमें मरने के लिए छोड़ दिया. ■

ललन यादव की पत्नी जनक दुलारी और भाई रमन यादव

सरजू बाई की खुदकुशी दुखद

सरजू बाई के पति उमराव सिंह और बेटा अचल सिंह

सीहोर ज़िले की आष्टा तहसील के लासुल्या सूखा गांव निवासिनी 60 वर्षीय सरजू बाई ने आत्महत्या कर ली. उनके पति उमराव सिंह (70) बताते हैं कि पत्नी ही खेती-बाड़ी का सारा काम संभालती थीं. वह बीमार रहते हैं. बेटा पूर्व में गांव का सरपंच रह चुका है. मालवा क्षेत्र में महिलाएं ही खेती-बाड़ी का काम संभालती हैं. सरजू बाई के बेटे एवं पूर्व सरपंच अचल सिंह ने बताया, परिवार के ऊपर 10 लाख रुपये का कर्ज था. हमने 12-15 एकड़ ज़मीन में सोयाबीन की खेती की थी. 10 क्विंटल बीज लगे थे. लेकिन, जब फसल कटकर घर आई, तो कुल छह बोरी सोयाबीन हाथ लगा. खेती में लगातार घाटा मां से देखा नहीं गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली. पहले लगभग 200 क्विंटल उपज हो जाती थी, लेकिन पिछले दो-तीन साल से खेती हुई नहीं. पानी भी नहीं है. गांव की आधी ज़मीन पानी की कमी के चलते ख़ाली पड़ी है, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली. पानी की कमी दूर करने के लिए 650 फुट बोर कराया, लेकिन तब भी पानी नहीं निकला. बोर ऐसा है कि लगातार एक घंटे पानी नहीं दे पाता. किसान के लिए खेती करना मजबूरी हो गई है, चाहे घाटा हो या फ़ायदा. जुए की तरह उसे जुटना ही पड़ता है. किसान इस आस में खेती करता जाता है कि कभी तो उसके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उस दिन की आस में उसके जीवन के दिन ख़त्म हो जाते हैं. ■

बदहाल अन्नदाता का खुशहाल मुख्यमंत्री

सीहोर ज़िले की आष्टा जनपद पंचायत के गांव पटारिया गोयल में सात नवंबर, 2015 को 38 वर्षीय किसान जीवन सिंह मेवाड़ा ने घर के पास स्थित खजूर के पेड़ पर खुद को फांसी लगा ली. आज उनका परिवार परेशानी में है, लेकिन सरकार की ओर से उसे कोई मदद नहीं मिल रही है. उनकी पत्नी नगीना (35) ने बताया, इस साल पहले ही सोयाबीन की फसल कम थी, लेकिन ज़्यादा बारिश की वजह से वह भी गल गई. ढाई बीघा ज़मीन में केवल 40 किलो उपज हुई. खेती के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से 50 हज़ार रुपये का लोन लिया था, इसके अलावा 14 हज़ार रुपये का बिजली बिल बकाया था. पिछले दो साल से बच्चों के स्कूल की फीस बकाया थी, किसी तरह व्यवहार में बच्चे पढ़ रहे थे. स्कूल वालों को फसल आते ही पूरी फीस देने का वादा किया था. भैंस खरीदने के लिए लोन लिया था. इसके अलावा कुछ कर्ज साहूकारों का भी था. लेकिन जब कई दिनों तक हुई बारिश के कारण खेत में फसल गल गई, तो वह अचानक घर से रस्सी लेकर निकले. हमें अंदाज़ा नहीं हुआ कि वह कहां जा रहे हैं. किसी ने नहीं सोचा था कि वह कुछ ऐसा-वैसा कर लेंगे. लेकिन, थोड़ी देर बाद लोगों ने बताया कि उन्होंने खजूर के पेड़ पर फांसी लगा ली है. जीवन के घर में पत्नी नगीना के अलावा बेटी भावना (15), बेटे सुधीर (13) और सुमित (10) सहित कुल चार लोग हैं. कर्ज का बोझ परिवार के सिर पर बना हुआ है. इनमें से कोई भी इतना सक्षम नहीं है, जो परिवार का खर्च चला सके. आज परिवार पाई-पाई के लिए मोहताज है. पेट भरने के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि उनके राज में प्रदेश का अन्नदाता खुशहाल है, लेकिन किसानों की बदहाली उस दावे का पर्दाफाश करती है.

मरहूम जीवन सिंह मेवाड़ा की पत्नी नगीना, बेटी भावना, बेटे सुधीर और सुमित

जीवन द्वारा आत्महत्या करने के बाद नेताओं का वहां जमघट लग गया, लेकिन पीड़ित परिवार को गांव वालों की कोशिश के बावजूद सरकार की तरफ़ से कोई मदद नहीं मिली. स्थानीय विधायक रणजीत सिंह गुणवान भी घटना के बाद आए थे. उन्होंने परिवार को पांच हज़ार रुपये देने की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार को इसके लिए लिख रहा हूं. जब मदद के लिए राशि मेरे खाते में आ जाएगी, तो ही दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा. वह राशि पीड़ित परिवार को नहीं ही मिली. स्थानीय निवासी राजन मेवाड़ा बताते हैं, मैं जीवन सिंह की पत्नी को लेकर एसडीएम के पास गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी है. हमारा काम ख़त्म हो गया है, अब जो करना है, सरकार को करना है. यह है प्रशासनिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा! ■

(शेष पृष्ठ 6 पर)

आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार की व्यथा-कथा

उनकी पीड़ा नसों में तेज़ाब...

पृष्ठ 5 का शेष

बेटे की मौत के बाद अब घर में ताला भी नहीं लगता

साल 2015 के भादो में गणेश चतुर्थी के दिन (17 सितंबर) सागर ज़िले के देवरी तहसील के डोंगर सलैया गांव निवासी राजाराम उर्फ रज्जू आदिवासी नामक 30 वर्षीय किसान ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली. गांव से एक किलोमीटर दूर एकांत में रज्जू का घर है, जहां आम तौर पर कोई आता-जाता नहीं है. जब हम उसके उस खपरैल वाले कच्चे घर पहुंचे, तो वहां कोई नहीं था. घर में ताला भी नहीं लगा था. गांव के एक वृद्ध की मदद से हम उसके घर पहुंचे थे. जब हमने उसके पड़ोसी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी मायके गई है और मां-बाप खेत में मज़दूरी करने गए हैं. घर में ताला न लगा होने की बात पर पड़ोसी ने कहा कि घर में कुछ है ही नहीं, तो ताला क्यों लगे. घर में एक-दो किलो आटा भी नहीं रहता. हम बुजुर्ग दंपति से मिलने खेत तक जा पहुंचे. वहां राजाराम की मां और पिता चने की कटाई कर रहे थे. पिता बात करने नहीं आए. मां शिवरानी हम तक पहुंचीं. उन्होंने बताया कि उनके पास क़रीब तीन एकड़ ज़मीन है. जब राजाराम ने आत्महत्या की थी, तब हमने खेत में धान और सोयाबीन लगाया था. उसके ऊपर 50 हज़ार रुपये का कर्ज था. सोयाबीन और धान की फसल सूख जाने के कारण वह सदमे में था और कर्ज को लेकर वह काफी दिनों से परेशान था. उसकी आत्महत्या के बाद अब उनका कोई सहारा नहीं है, बुढ़ापे में मज़दूरी करके पेट पालना पड़ रहा है. ■

मरहूम राजाराम की मां शिवरानी

आखिर कितनी मौतें देखेंगी सियारानी!

नरेंद्र लोधी (इनसेट) की मां सियारानी

जिस दिन सारा देश दुर्गा नवमी की चकाचौंध और दशहरे की तैयारियों में डूबा हुआ था, उसी दिन सागर ज़िले के सूरा देही गांव निवासी नरेंद्र लोधी नामक 20 वर्षीय किसान ने आत्महत्या कर ली थी. वह लगातार इस चिंता में था कि उसके खेत में लगी प्याज की पौध सूख जाएगी, तो वह क्या करेगा, क्योंकि नवमी के दिन बिजली विभाग के लोग अचानक नरेंद्र के घर आए थे और बिजली बिल का बकाया 12 हज़ार रुपये देने के लिए दबाव बना रहे थे. बिजली वाले खेत के बोर में लगी मोटर भी निकाल ले गए और कह गए कि चाहे मर जाओ, फांसी लगा लो, अब पैसे न मिलने तक मोटर नहीं मिलेगी. नरेंद्र सदमे में आ गया. नरेंद्र के पिता शालिग्राम का लगभग तीन साल पहले और बड़े भाई यशवंत का दो साल पहले खेत में करंट लगने की वजह से देहांत हो चुका था. मां सियारानी (50), बड़े भाई यशवंत की पत्नी और तीन बेटियों की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर थी. जब कर्ज से उबरने का कोई रास्ता नरेंद्र को नहीं दिखा, तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. नरेंद्र की मां सियारानी बताती हैं कि उस पर सरकारी बैंकों, रिश्तेदारों और साहूकारों का कुल तीन-चार लाख रुपये का कर्ज था. प्रशासन ने इस मौत पर कहा कि जुए में हारने की वजह से नरेंद्र ने फांसी लगाई. आख़िरकार ज़िला प्रशासन ने नरेंद्र की मौत का सच स्वीकार किया, पर पीड़ित परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली. घर में दो विधवाएं हैं और तीन बेटियां. समाज के सामने बड़ा प्रश्न है कि आख़िर उनका घर कैसे चले, क्योंकि उनके पास अब कोई सहारा नहीं बचा है. ■

मां के सामने बहुत रोया था राजकुमार

सागर ज़िले की जैसीनगर तहसील के सरखड़ी गांव निवासी 24 वर्षीय किसान राजकुमार अहिरवार के पास दो एकड़ ज़मीन थी. उसने कर्ज लेकर अपने खेत में सोयाबीन और उड़द की बोवनी की थी, लेकिन पानी की कमी के चलते सारी फसल सूख गई. फसल खराब होने की वजह से वह डिप्रेशन में चला गया. वह घर आकर मां प्रेम बाई के पास रोता रहा. मां ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि कर्ज चुकाने के लिए हम मज़दूरी कर लेंगे, फसल नहीं हुई, तो कोई बात नहीं. लेकिन, उसने कहा कि अब हमारे दिन कभी भी नहीं फिरेंगे. उसने सोचा था 10-12 बोरी सोयाबीन निकल आएगा, तो मंडी में बेचकर कर्ज चुका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सात अक्टूबर, 2015 को सुबह वह खेत पर चला गया और वहां लगे बेर के पेड़ पर खुद को फांसी लगा ली. गांव में फसल कटाई के लिए बाहर से आए मज़दूरों ने खेत में लगे पेड़ पर राजकुमार का शव लटकता देखा, तो पुलिस को सूचना दी. राजकुमार के बड़े भाई भागचंद ने बताया कि खेत पर कपिलधारा का कुआं खुदा, लेकिन पूरा होने से पहले ही पट गया. सरकार की ओर से एक एकड़ का 15 सौ रुपये मुआवज़ा मिला. पुलिस ने केस दर्ज किया कि राजकुमार ने फसल देखकर खेत में फांसी लगा ली, लेकिन प्रशासन ने इसे किसान की आत्महत्या नहीं माना. तहसीलदार जांच के लिए आए और उन्होंने कहा कि वह पूरी मदद करेंगे, लेकिन आज तक किसी तरह की मदद नहीं मिली. ■

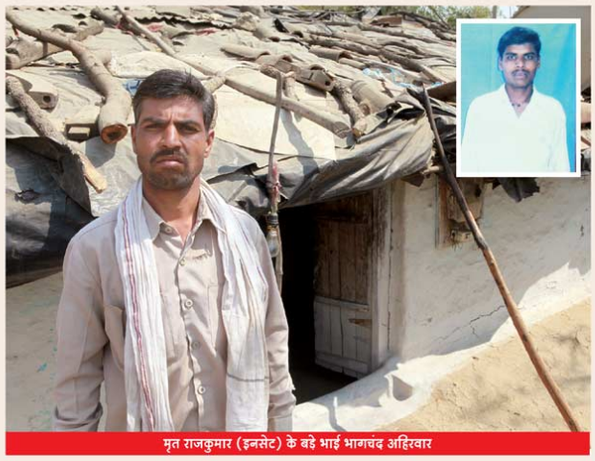

मृत राजकुमार (इनसेट) के बड़े भाई भागचंद अहिरवार

(शेष पृष्ठ 7 पर)

आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार की व्यथा-कथा

उनकी पीड़ा नसों में तेज़ाब...

पृष्ठ 6 का शेष

किस्सू के आज़ाद होने का क़िस्सा

किस्सू अहिरवार की पत्नी उमा और बच्चे

जिस दिन देश अपनी आज़ादी की 69वीं वर्षगांठ बना रहा था, उसी दिन दमोह ज़िले के मड़ियादो गांव निवासी किसान किस्सू अहिरवार (30) ने खेत स्थित कुएं में कूदकर अपनी समस्याओं से आज़ादी पा ली. किस्सू अपने पीछे त्रासद जीवन जीने के लिए अपनी विधवा, तीन बेटियां और दो बेटे छोड़ गए. किस्सू की विधवा उमा देवी बताती हैं, जिस समय यह हादसा हुआ, हमारे खेत में सोयाबीन लगा था. खेती खराब हो गई थी, इस वजह से वह टेंशन में थे. खेतों में पांच बोरी सोयाबीन लगाया था, लेकिन निकला एक भी नहीं. 12 हज़ार रुपये की लागत लगी थी, वह भी नहीं निकली. सात लोगों का परिवार कैसे चलेगा, यही चिंता उन्हें खाए जा रही थी. ऊपर से कर्ज भी था. सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली. कोई ख़बर लेने तक नहीं आया. आज मुझे बच्चों के साथ मज़दूरी करके पेट पालना पड़ रहा है. मैं और मेरी तीनों बेटियां खेत काट रहे हैं. मुझे 120 और बच्चों को 50-50 रुपये दिन के मिल जाते हैं, किसी तरह खर्च चल रहा है. सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए, राहत देनी चाहिए. ■

'किसान तो कर्ज मा मरो जा रओ है...'

होशंगाबाद ज़िले के ग्राम सेमखेड़ा निवासी 45 वर्षीय खेतिहर मज़दूर अमान सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह किरार ने पांच फरवरी, 2015 को खेत के क़रीब स्थित सागौन के पेड़ पर फांसी लगा ली. उनकी पत्नी सुमंतरा बाई बताती हैं, हमारे पास कुल 40 डिसमिल ज़मीन है. पति ने कुछ खेती बटाई पर ली थी. अपनी खेती करने के अलावा वह दूसरों के खेतों में मज़दूरी करते थे. उनके ऊपर लगभग डेढ़ लाख रुपये का कर्ज था. पिछले कुछ सालों से उपज नहीं हो रही थी. मज़दूरी से घर चल रहा था. कर्ज देने वाले लोग आएदिन तगादा करने आते थे, इसलिए उन्हें कर्ज चुकाने की चिंता रहती थी. उनकी बातों से कभी ऐसा नहीं लगा कि वह आत्महत्या जैसा क़दम उठा लेंगे. उस दिन रात में वह बटाई वाले खेत में पानी लगाने गए थे. सुबह उनका शव सागौन के पेड़ पर लटकता मिला. सुमंतरा कहती हैं, किसान तो कर्ज में मरो जा रओ है, जीन के पास जित्ती खेती है, बा के ऊपर उत्तोई कर्ज है. खेती में कछु हो नहीं रओ है, तो किसान करे, तो का करे. ■

अमान सिंह किरार की पत्नी सुमंतरा बाई

पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ही नहीं दी

होशंगाबाद ज़िले के बनखेड़ी ब्लॉक स्थित गांव चांदौन निवासी 45 वर्षीय किसान अशोक शर्मा ने 19 नवंबर, 2014 को अपने खेत में सल्फास खाकर जान दे दी. अशोक शर्मा के पास दो एकड़ ज़मीन थी. तक़रीबन 60 हज़ार रुपये का बैंक कर्ज था. इसके अलावा उन्होंने साहूकारों से भी कर्ज ले रखा था. जिस समय यह घटना हुई, खेत में सोयाबीन लगा था और बारिश की वजह से खेती खराब हो गई थी. उनके बेटे हेमंत शर्मा बताते हैं, घटना के पांच-छह दिन पहले वह घर से बिना बताए कहीं चले गए थे. उस वक्त वह परेशान थे. कहां गए थे, पता नहीं चला. लेकिन, उस दिन उन्होंने मुझे फोन करके खेत पर बुलाया. वहां जाकर देखा, तो उन्होंने ज़हर खा लिया था. उनकी सांसें चल रही थीं. मैं उन्हें बनखेड़ी अस्पताल ले गया, फिर चांदौन ले गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. आज तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं मिली, जिसके आधार पर हम सरकार से मुआवज़ा मांग सकें. ■

मौत से तो बच गए ज़िंदगी से कैसे बचेंगे!

महेंद्र पटेल अपनी पत्नी पुष्पा और बच्चे के साथ

कीटनाशक पीकर भी बच गए बब्बू अहिरवार

दमोह ज़िले के सुम्मेर गांव निवासी 32 वर्षीय महेंद्र पटेल ने पांच साल पहले फसल बर्बाद होने की वजह से ज़हर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी. उन्होंने बताया कि उस साल पाला पड़ने की वजह से फसल खराब हो गई थी. मेरे हिस्से में पांच एकड़ ज़मीन थी. मैं नौवीं पास हूं, मेरे पास खेती करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था. मैंने खेत में मसूर बोई थी. सारी फसल खराब देखकर मेरा दिमाग़ खराब हो गया. मेरे ऊपर साहूकार का ढाई लाख रुपये का कर्ज था. 80-90 हज़ार रुपये बैंक कर्ज था. फसल खराब हो गई थी, कोई मुआवजा नहीं मिला था. साहूकार आएदिन तगादा करने चले आते थे. इसलिए मुझे इन झंझटों से निकलने का एक ही रास्ता नज़र आया और मैंने सोयाबीन में डाली जाने वाली कीटनाशक दवा पी ली. लोग मुझे अस्पताल ले गए और मैं बच गया. बाद में जांच के लिए भोपाल से एक टीम आई, तहसीलदार भी जांच के लिए आए. तहसीलदार ने पांच हज़ार रुपये का चेक दिया और कहा कि अपना इलाज कराओ. अब भी किसानों की वही स्थिति बनी हुई है. पहले तीन साल सूखा पड़ा, तो फसल नहीं हुई, पिछले साल अतिवृष्टि के चलते फसल खराब हो गई. ऐसे में किसान क्या करे? सरकार का रवैया किसानों के प्रति बेहद खराब है. राहत के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है. किसान अंदर से खोखला हो गया है.

इसी तरह सागर ज़िले की जैसीनगर तहसील के शोभापुर गांव निवासी बब्बू अहिरवार ने पिछले साल कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की. वह खुशकिस्मत थे कि बच गए. बब्बू कहते हैं, मेरे ऊपर डेढ़ लाख रुपये का कर्ज था. फसलें नष्ट हो चुकी थीं. मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था. मैंने ठेके पर 10 एकड़ ज़मीन ली थी, जिस पर सोयाबीन लगाया था. बारिश की वजह से पूरी फसल खराब हो गई. कटाई कराने पर कुछ भी नहीं निकला. मैंने अपनी तकलीफ से मुक्ति पाने के लिए सोयाबीन में डाला जाने वाला कीटनाशक पी लिया, लेकिन बच गया. ■

धोखे की बुनियाद पर कृषि कर्मण पुरस्कार

किसानों के प्रति अकर्मण्य सरकार

सोरिन शर्मा

मध्य प्रदेश सरकार फसलों की बर्बादी को किसानों की आत्महत्या का एकमात्र कारण नहीं मानती. गेहूं उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार हथियाने वाली सरकार को यह बताना ज़रूरी है कि फसलें बर्बाद हुईं, तो अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन कैसे हुआ? सरकार इस सवाल से बचना चाहती है.

वन उपज के साथ ही कृषि मध्य प्रदेश का प्रमुख व्यवसाय है. पिछले चार साल से लगातार प्रदेश में अनियमित वर्षा हुई. कभी अचानक बाढ़ के हालात बने, तो कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ गया. दोनों ही स्थितियों में किसानों को भारी नुक़सान उठाना पड़ा. मालवा के अलावा भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खंडवा आदि ज़िलों में सूखे की स्थिति पैदा हुई, गेहूं एवं दलहन की फसलों को भारी नुक़सान हुआ. कहने को तो सरकार सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध कराने में रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रही है, परंतु न तो किसानों को समय पर पर्याप्त बिजली मिल पाती है और न नहरों या अन्य माध्यम से पानी. यही कारण है कि वर्षा कम होने पर फसलें सूख जाती हैं.

सूखा या असमय ओलावृष्टि से लगातार फसलों को नुक़सान होता आ रहा है. इसके चलते साल की दोनों फसलें प्रभावित हो जाती हैं. बीज, सिंचाई, खाद, बिजली के भारी-भरकम बिल चुकाने के लिए जब पैसे की आवश्यकता होती है, तो कर्ज लेना पड़ता है. मध्य प्रदेश सरकार किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने का दावा भी कर रही है, परंतु वास्तविकता यह है कि राज्य का प्रत्येक किसान कर्जदार है. उस पर राज्य के सहकारी बैंकों का ही नहीं, सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों का कर्ज भी चढ़ा हुआ है. इस सच्चाई को सरकार लगातार छिपाने का प्रयास करती है, परंतु यही किसानों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण बन रही है. पिछले पांच सालों के दौरान यदि सरकार को तीन साल लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला तो दूसरी ओर लगभग पांच हज़ार किसानों ने आत्महत्या कर ली.

हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी भोपाल के समीप प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना का लोकार्पण किया. इस बीमा योजना के पहले भी किसान बीमा योजना थी, परंतु किसानों से इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम तो अधिक ले लिया जाता है, उसके बदले जब फसल खराब होती है, तो बीमा राशि का भुगतान देखकर शर्मिंदगी का अनुभव होता है. इस साल किसानों की पूरी फसल चौपट हुई, लेकिन बीमा राशि प्रति हेक्टेयर 126 रुपये, तो किसी को 256 रुपये दी गई. कई किसानों को तो 12 रुपये तक बीमा राशि का भुगतान किया गया. दूसरी ओर जब बैंक अधिकारी-कर्मचारी उनसे वसूली करने पहुंचते हैं, तो प्रदेश सरकार के अधिकारी उन्हें रोकने के बजाय उनके साथ कुर्की करने पहुंच जाते हैं.

मध्य प्रदेश में अधिकांश किसानों ने कर्ज में डूबने के कारण आत्महत्या की. प्रमुख कारण बढ़ता कर्ज और घटता उत्पादन रहा, लेकिन पुलिस को सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि इन्हें मुख्य कारण के रूप में कतई न दिखाया जाए. बीमारी, परिवार की समस्या या अन्य कोई ऐसा कारण आत्महत्या के पीछे दिखाया जाए, जिससे यह सिद्ध न हो सके कि फसल खराब होने या कर्ज वसूली के लिए प्रताड़ित करने के कारण किसान ने आत्महत्या की. प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन कहते हैं कि किसान अपनी करनी के कारण मर रहे हैं. इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है. वह दावा करते हैं कि प्रदेश में कोई भी किसान फसल खराब होने के कारण नहीं मरा. मध्य प्रदेश सरकार किसानों की भरपूर सहायता कर रही है.

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण यादव कहते हैं कि यदि मुख्यमंत्री किसान पुत्र हैं, तो फिर प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? किसानों को राहत स्वरूप कुछ भी नहीं मिल पाया. इतना भी नहीं कि वे अगली फसल के लिए बीज खरीद सकें. बाकी व्यवस्थाएं तो दूर की बात है. यदि सरकार किसानों को पैसा बांट रही होती, तो हर दूसरे-तीसरे दिन किसान आत्महत्या क्यों कर रहे होते? प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर का कहना है कि महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं. पिछले तीन सालों के दौरान तीन हज़ार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, जिसका रिकॉर्ड पुलिस के पास है, लेकिन सरकार छिपा रही है. राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में किसानों को आज भी राहत नहीं मिल सकी है. फसल बीमा के नाम पर बीमा कंपनियों ने घोटाला किया.

किसानों के हज़ारों करोड़ रुपये का गोलमाल हुआ. इसकी राज्य और केंद्र सरकार को जांच करानी चाहिए. किसानों से कर्ज वसूली स्थगित करने का ढोंग किया जा रहा है. सही बात तो यह है कि हर तीसरे दिन किसानों से कर्ज वसूलने केलिए बैंकों के कर्मचारी पहुंच रहे हैं. इनमें राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सहकारी बैंक भी शामिल हैं. गुर्जर कहते हैं कि अस्सी प्रतिशत किसानों को सरकार के जीरो प्रतिशत ब्याज के कर्ज का लाभ नहीं मिल पा रहा है. यह भी एक छलावा है, क्योंकि या तो किसान समय पर कर्ज नहीं चुका पाता है या फिर समय पर किस्त नहीं दे पाता है, जो इसकी प्रमुख शर्तें हैं. हर तीसरे दिन आत्महत्या करते किसानों को सरकार नहीं रोक पा रही है, क्योंकि उसके पास कोई ठोस नीति नहीं है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

देश और संसद का माहौल ख़राब हो रहा है

सरकार मेक इन इंडिया और व्यवसाय में आसानी जैसी बातें कर रही है, लेकिन छोटे एवं मध्य वर्ग के व्यवसाय के लिए माहौल सही नहीं है. सरकार ने आभूषणों पर एक फ़ीसद एक्साइज टैक्स लगा दिया, बिना यह विचार किए कि छोटे सर्राफा व्यापारियों के पास इस एक फ़ीसद कर का हिसाब लगाने की कोई विधि तक नहीं है. इसे उन व्यापारियों पर लागू किया जा सकता है, जिनका टर्नओवर एक खास सीमा के ऊपर है. आंख बंद करके हर किसी को, जिसमें लाखों आभूषण कारीगर भी शामिल हैं, इसमें शामिल नहीं करना चाहिए. इसे बिना उचित जांच-पड़ताल के लागू कर दिया गया है.

बजट सत्र का पहला हिस्सा सम्पन्न हो गया. इसके दो पहलू हैं. अच्छा पहलू यह है कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान कम उत्पन्न हुआ. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बेहतर आपसी समझ के चलते सदन ठीक से चला. यह अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में संसद आम आदमी की सोच को दर्शाती है. पिछले दो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू की गई परम्परा, जिसके तहत संसद नहीं चलने दी जाती थी, का बोलबाला था. कांग्रेस ने यह काम भाजपा की तुलना में बेहतर तरीके से किया, जिसके लिए उसकी आलोचना भी हुई. इससे बढ़कर यह कि सरकार की तरफ़ से एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया कि ग़ैर निर्वाचित लोग निर्वाचित लोगों की राह या काम में बाधा बन रहे हैं. यह बात सही नहीं है, क्योंकि संविधान में दो सदनों का प्रावधान किया गया है. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो पहले न हुआ हो. पहले भी ऐसा हुआ है कि सरकार लोकसभा में कई बिल पारित नहीं करा पाई. इसका उपाय यह है कि आप द्विपक्षीय बात कीजिए और आपसी सहमति से मामला सुलझा लीजिए. संसद में हंगामा कम होना चाहिए, भले टीवी चैनलों में ज़्यादा हो. हमें उम्मीद करनी चाहिए कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में भी रचनात्मक काम होगा. एक पुरानी कहावत है कि विपक्ष को अपनी बात कहने देना चाहिए और सरकार को अपना काम निकालने के लिए रास्ता तलाशते रहना चाहिए. आख़िरकार आपके पास बहुमत है, आप विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौक़ा दीजिए.

लेकिन, इस पूरे पक्ष का नकारात्मक पहलू यह है कि जो बिल पारित हुए हैं, उनकी पूरी तरह जांच-परख नहीं हुई है. रीयल एस्टेट बिल क्यों पारित हुआ, यह समझ से बाहर है. यह राज्य का विषय है. दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों की बात तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र एवं गुजरात जैसे राज्य रीयल एस्टेट से जुड़े अपने नियम खुद बना लेते हैं. लेकिन, अगर आप ऐसे क़ानून बनाते हैं, जिसका पालन करना या लागू करना बहुत मुश्किल हो, तो इससे और अधिक दिक्कतें पैदा होने लगती हैं. इसलिए बिना ठीक से समझे-बूझे कोई बिल पारित कर देना अच्छी बात नहीं है. इसी तरह आधार बिल है, जो बहुत विवादास्पद है. बेशक, यह यूपीए द्वारा लाया गया था और अब एनडीए सरकार इसे पारित कराना चाहती थी. यह ऐसा है, जैसे आप किसी शख़्स का पीछा कर रहे हैं. ऐसा तानाशाही वाली शासन व्यवस्था में होता है, किसी लोकतंत्र में नहीं होता. ग़रीबों की सहायता की आड़ में आप हर शख़्स को एक नंबर दे रहे हैं. यह काम बीपीएल सूची के ज़रिये भी किया जा सकता था. भारत के हर नागरिक को अपने फिंगर प्रिंट, आंख की पुतली के निशान और फोटो देने पड़ रहे हैं, जो ठीक नहीं है. आप बहुत क़ीमती जानकारियां ऐसे लोगों के हाथों में दे रहे हैं, जो आसानी से उनका दुरुपयोग कर सकते हैं. देखते हैं, यह कैसे काम करता है.

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा विजय माल्या का लंदन जाना है. लोग कह रहे हैं कि वह भाग गए. लेकिन, एटॉर्नी जनरल ने सच्चाई लोगों के सामने यह कहकर रख दी कि वह भगोड़े नहीं हैं, किसी भी अदालत से वांछित नहीं हैं. उनके ख़िलाफ़ गिरफ्तारी का कोई वारंट नहीं है. वह एक आज़ाद नागरिक हैं. सबसे बढ़कर यह कि वह एक सांसद हैं. यह सही है कि उनकी कंपनी पर बैंकों का बहुत बड़ा कर्ज है, जो एक आपराधिक मामला नहीं है. बैंक अपनी आंखें खोलकर कर्ज देते हैं. माल्या ने रात के अंधेरे में कर्ज नहीं लिया था. फिलहाल जो कर्ज दिखाया जा रहा है, वह नौ हज़ार करोड़ रुपये का है. कहा जा रहा है कि माल्या स्टेट बैंक के चेयरमैन के पास गए और यह पेशकश की कि दूसरे कॉरपोरेट हाउसेज के कर्ज के लिए जो मापदंड अपनाया गया है, वही उनके लिए भी अपनाया जाए. इसके मुताबिक, उनका कर्ज चार हज़ार करोड़ रुपये बनता है, जो वह अभी चुकाने के लिए तैयार हैं. लेकिन, स्टेट बैंक के चेयरमैन ने उनकी पेशकश ठुकरा दी और कहा कि यह मापदंड आप पर लागू नहीं होता. सवाल है कि अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मापदंड क्यों? क्या वह भाजपा के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले अमित शाह या दूसरे लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए? परेशानी क्या है? मैं किसी शख़्स की तरफ़दारी नहीं कर रहा हूं. आप वातावरण खराब कर रहे हैं. आप विदेशियों को भारत में निवेश के लिए बुला रहे हैं. इससे विदेशी निवेशकों के मन में भारत को लेकर किस तरह की छवि बनेगी? कल तक एक बड़े उद्योगपति, जो अभी भी एक सांसद हैं, जिनके क्लाइंट्स में सांसद भी शामिल थे, जिनकी विमानन सेवा बेहतरीन मानी जाती थी, के साथ आप आज किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? अगर आप वाकई चाहते हैं कि निवेश हो, उद्योग आए, तो पूरा वातावरण बदलने की ज़रूरत है.

ग़रीबों की सहायता की आड़ में आप हर शख़्स को एक नंबर दे रहे हैं. यह काम बीपीएल सूची के ज़रिये भी किया जा सकता था. भारत के हर नागरिक को अपने फिंगर प्रिंट, आंख की पुतली के निशान और फोटो देने पड़ रहे हैं, जो ठीक नहीं है. आप बहुत क़ीमती जानकारियां ऐसे लोगों के हाथों में दे रहे हैं, जो आसानी से उनका दुरुपयोग कर सकते हैं. देखते हैं, यह कैसे काम करता है.

सरकार मेक इन इंडिया और व्यवसाय में आसानी जैसी बातें कर रही है, लेकिन छोटे एवं मध्य वर्ग के व्यवसाय के लिए माहौल सही नहीं है. सरकार ने आभूषणों पर एक फ़ीसद एक्साइज टैक्स लगा दिया, बिना यह विचार किए कि छोटे सर्राफा व्यापारियों के पास इस एक फ़ीसद कर का हिसाब लगाने की कोई विधि तक नहीं है. इसे उन व्यापारियों पर लागू किया जा सकता है, जिनका टर्नओवर एक खास सीमा के ऊपर है. आंख बंद करके हर किसी को, जिसमें लाखों आभूषण कारीगर भी शामिल हैं, इसमें शामिल नहीं करना चाहिए. इसे बिना उचित जांच-पड़ताल के लागू कर दिया गया है. बेशक, वित्त मंत्री और संबंधित लोगों के पास इसके लिए समय नहीं है.

तीसरा दिलचस्प मुद्दा आनंद बाज़ार पत्रिका का उत्तर प्रदेश चुनाव पर आया सर्वे है. हालांकि, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत समय है और किसी तरह की भविष्यवाणी करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी. लेकिन, इस सर्वे ने बहुजन समाज पार्टी को अच्छी-खासी बढ़त दे दी है. एक वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है, लेकिन आम लोगों की भी कुछ यही सोच है कि उत्तर प्रदेश में मायावती सबसे आगे रहेंगी. वह कितनी आगे रहेंगी, दूसरे नंबर पर कौन होगा, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा. देखते हैं, क्या होता है? ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

जनता करे चुनाव

दिनोंदिन बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है कि ज़िला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख भी सीधे जनता द्वारा चुने जाएं. वर्तमान व्यवस्था में ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी को प्रति वोट दो लाख और ज़िला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को 10 से 15 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं. यानी जीतने के लिए तक़रीबन चार-पांच करोड़ रुपये का खर्च. जरा सोचिए, जो शख़्स चुनाव में चार-पांच करोड़ रुपये खर्च करेगा, वह निश्चित तौर पर इससे तीन-चार गुनी रकम पैदा करने का प्रयास करेगा. ऐसा नहीं है कि विकास कार्य नहीं होंगे. विकास कार्य होंगे, लेकिन इतने घटिया कि सड़कें छह महीने में उखड़ जाएंगी, पुल ध्वंस जाएंगे, स्कूलों-अस्पतालों के निर्माण में सीमेंट की जगह बालू इस्तेमाल होगी और प्लास्टर में सीमेंट-बालू का अनुपात 1:10 होगा. ज़िला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख को सीधे जनता द्वारा चुने जाने में आख़िर किसे और क्या आपत्ति है? न प्रत्याशी अनाप-शनाप खर्च करेंगे और न वे जीतने के बाद हद से ज़्यादा लूटेंगे.

-राज किशोर पांडेय, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

अनुचित तुलना

किसानों द्वारा आत्महत्या को शहादत मानना या आत्महत्या करने वाले किसानों को शहीद बताना ग़लत है. सीमा पर जान देने वाले सैनिक शहीद इसलिए कहलाते हैं, क्योंकि वे विषम परिस्थितियों में मातृभूमि की रक्षा कर रहे होते हैं, जबकि किसानों द्वारा आत्महत्या परिस्थितियों से पलायन है. आज जबकि किसी भी आपदा के चलते फसल नष्ट होने पर मुआवजे की राशि बढ़ा दी गई है और खाद-बिजली की उपलब्धता के मामले में पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है, तो ऐसे में किसानों द्वारा आत्महत्या की तुलना सैनिकों की शहादत से करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है.

-ओम वर्मा, *देवास, मध्य प्रदेश.*

सांसद अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं

जब तोप मुक़ाबिल हो-संसद की गरिमा से खिलवाड़ बंद कीजिए (14-20 मार्च, 2016) पढ़ा. चौथी दुनिया निर्भीकता के साथ सच्चाई लिखता है, जो सराहनीय है. संसद में मुद्दों पर बहस और काम से अधिक जंग देखने को मिलती है. सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों इसमें शामिल रहते हैं. सांसदों को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए जनता के दु:खों-हितों के बारे में संसद में चर्चा करनी चाहिए.

-राहुल कुमार, *दानापुर, बिहार.*

आम बजट महज एक छलावा

कवर स्टोरी-बाजीगरी या धोखाधड़ी (14-20 मार्च, 2016) ने प्रभावित किया. एसएन विशाल ने साफ़ कर दिया कि आम बजट जनता के साथ धोखा है. सरकार जो दावे कर रही है, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य मंत्री खूब बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आम बजट में कोई बड़ी बात नहीं दिखाई दी. सरकार अब बहाना नहीं बना सकती कि गठबंधन सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं, क्योंकि भाजपा को स्वयं बहुमत हासिल है.

-अमित सिंह, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

आंकड़ों की बाजीगरी

स्तंभ-पद की मर्यादा समझें मोदी (14-20 मार्च, 2016) ने काफी प्रभावित किया. वास्तव में बजट भाषण ने यह ज़ाहिर करने का प्रयास किया कि कृषि क्षेत्र में एक बड़ा निवेश होने जा रहा है. लेकिन, यह बात पूरी तरह सच नहीं है. सरकार ने जनता को आंकड़ों में उलझाने का प्रयास किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि वह एक ग़रीब परिवार से हैं और ग़रीबों का दु:ख-दर्द अच्छी तरह जानते-समझते हैं, लेकिन आम बजट से ऐसा नहीं लगता कि सरकार ग़रीबों का दु:ख-दर्द दूर करना चाहती है.

-नीतीश यादव, *कटिहार, बिहार.*

आरक्षण के नाम पर विध्वंस

स्टोरी-जाट और ग़ैर जाट में बंटा हरियाणा (14-20 मार्च, 2016) ने जाट आंदोलन की सच्चाई पर बखूबी रोशनी डाली. यह आंदोलन एक सोची-समझी साज़िश का परिणाम था, इसमें कोई दो राय नहीं है. कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ने इसे अपने-अपने तरीके से भुनाया और फ़ायदा उठाने की कोशिश की. इस आंदोलन के चलते अरबों रुपये का नुक़सान हुआ. आंदोलन के नाम पर हरियाणा को जिस तरह बंधक बनाया गया, वह निंदनीय है.

-संदीप सिंह महाला, *फरीदाबाद, हरियाणा.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

यह मुलायम-अखिलेश दोनों की अग्निपरीक्षा है

> अखिलेश यादव सरकार के ज़्यादातर काम अफसरशाही के गलियारों में भटक कर अपना वजूद खो बैठे. अखिलेश यादव की छवि बहुत अच्छी है, लेकिन वह छवि तब बेअसर हो जाती है, जब क़ानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठने लगते हैं. हम अखिलेश यादव की इस बात से सहमत हैं कि यह स्थिति कमोबेश बहुत सारे प्रदेशों में है, लेकिन उन प्रदेशों में वहां की सत्ता या नेता से लोगों की उतनी अपेक्षाएं नहीं हैं, जितनी अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही जगा दीं.

एक टीवी चैनल ने सर्वे करने वाली एक विश्वसनीय संस्था के साथ मिलकर, उत्तर प्रदेश में आज चुनाव होते हैं, तो किसे कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी गणना की है. इस सर्वे ने बहुजन समाज पार्टी को प्रथम स्थान दिया है. भारतीय जनता पार्टी को दूसरा, समाजवादी पार्टी को तीसरा और कांग्रेस को चौथा स्थान मिला है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि यह प्रायोजित सर्वे है, जो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए कराया गया है. अखिलेश यादव की सधी हुई प्रतिक्रिया रही कि हमें सावधान हो जाना चाहिए. सबसे पहले हमने इसी बात की पड़ताल की कि क्या यह सर्वे निश्चित मानदंडों के आधार पर है या नहीं? और, हमारी जानकारी के हिसाब से यह सर्वे पूर्णतय: तय मानकों के आधार पर हुआ है. सर्वे सही है, भले ही यह कुछ लोगों को परेशान करे और कुछ लोगों को खुश.

मेरा अपना मानना है कि बहुजन समाज पार्टी ने पिछले चार वर्षों में ऐसा कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से लोग उसे वोट दें. उसने जनता की परेशानियों को लेकर कोई आंदोलन नहीं किया, आवाज़ तक नहीं उठाई. बजाय इसके कि गाहे-बगाहे बसपा की अकेली सर्वमान्य नेता मायावती जी समय-समय पर बयान देती रहीं. लेकिन, उन्होंने एक अच्छा काम किया कि वह पूरे चार वर्ष खामोश रहीं और उनकी खामोशी ने उन्हें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सहज विकल्प बना दिया. बहुजन समाज पार्टी पैसे देकर सर्वे कराने के लिए कभी पकड़ में नहीं आई और न उसने कभी ऐसी कोई रुचि दिखाई. इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप कि यह बहुजन समाज पार्टी या मायावती द्वारा प्रायोजित सर्वे है, ग़लत है.

सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात समाजवादी पार्टी के लिए है. अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, तब सभी को लगा था कि वह देश में नौजवानों के एकछत्र उदाहरण बनकर चमकेंगे. अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान जब डीपी यादव को पार्टी में न लेने का सार्वजानिक ऐलान किया, तो उनके इस क़दम को उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर सराहा और अखिलेश यादव के रूप में एक नए नेता में अपना पूर्ण विश्वास जताया. उत्तर प्रदेश को ऐसा बहुमत कभी-कभी मिला है. अखिलेश यादव के सामने कोई चुनौती नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अवसर थे. लेकिन, संभवत: अखिलेश यादव अपने सलाहकारों या प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से अपनी वह छवि नहीं बना पाए, जिसकी कल्पना चुनाव के समय लोगों ने की थी. परिणाम स्वरूप आज का यह सर्वे अखिलेश यादव के लिए सचमुच एक चेतावनी है.

अखिलेश यादव को कभी शहरों से वोट नहीं मिला और न शहर में उनके मतदाता हैं. उनके मतदाता गांवों में हैं, जिनकी आवश्यकता बिजली है, सड़क है, पानी है, स्कूल हैं और अस्पताल हैं. इस दिशा में अखिलेश यादव काम नहीं कर पाए. मेरा मानना है कि इसके पीछे उन प्रशासनिक अधिकारियों का हाथ है, जो बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी नाक के बाल बने हुए थे. बिजली की हालत सुधरी, लेकिन बिजली शहरों में आई, गांव में नहीं. गांवों के ट्यूबवेल सूने पड़े हैं. नहरें वह असर नहीं डाल पा रही हैं, जो किसान को खेती के लिए चाहिए. गांवों की सड़कें लगभग नहीं बनीं. स्कूल और अस्पताल के बारे में कहना क्या, क्योंकि वे तो सारे देश में ऐसे हैं. लेकिन, अखिलेश के सामने अवसर था कि वह उत्तर प्रदेश में स्कूलों और अस्पतालों की हालत सुधारते.

अखिलेश यादव के मतदाता मुखर तो हैं, लेकिन जो समर्थन उन्हें मिला, वह उनके वोटों के आधार से बाहर जाकर मिला. और, जिसने बाहर जाकर उन्हें समर्थन दिया, जो उनके समर्थकों के दायरे में नहीं आता, वह वर्ग आज निराश है, चिंतित है, परेशान है. शायद इसलिए उसने सर्वे में अखिलेश यादव के प्रति उदासीनता दिखाई.

अखिलेश यादव सरकार के ज़्यादातर काम अफसरशाही के गलियारों में भटक कर अपना वजूद खो बैठे. अखिलेश यादव की छवि बहुत अच्छी है, लेकिन वह छवि तब बेअसर हो जाती है, जब क़ानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठने लगते हैं. हम अखिलेश यादव की इस बात से सहमत हैं कि यह स्थिति कमोबेश बहुत सारे प्रदेशों में है, लेकिन उन प्रदेशों में वहां की सत्ता या नेता से लोगों की उतनी अपेक्षाएं नहीं हैं, जितनी अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही जगा दीं. लोगों को लगा कि विकास के काम अवश्य होने चाहिए. उनकी रोजमर्रा की ज़िंदगी, जिसका सीधा संबंध क़ानून व्यवस्था से है, कम से कम आसान हो जाएगी, स्थिति शांतिपूर्ण हो जाएगी. इसलिए अखिलेश यादव को क़ानून व्यवस्था के मोर्चे पर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और सर्वे में अखिलेश सरकार के प्रति नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह क़ानून व्यवस्था है.

भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ नरेंद्र मोदी के भरोसे है. वह अपना ऐसा कोई नेता उभार नहीं सकी, जो प्रदेश में पार्टी को लेकर चल सके. ले-देकर राजनाथ सिंह का नाम है, जो पुराना है. उसके बाद योगी आदित्य नाथ का नाम आता है, वरुण गांधी का नाम आता है. अब स्मृति ईरानी का नाम आने लगा है. अगर ये भाजपा के चेहरे बनकर प्रदेश में घूमेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, मैं नहीं कह सकता. हालांकि, भारतीय जनता पार्टी को सर्वे में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लोगों ने पसंद किया है. यह पसंद कहीं यहीं तक न रह जाए, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए, क्योंकि बिहार में अभी ऐसा हो चुका है.

कांग्रेस न पहले चिंतित थी, न अभी चिंतित है. उसे लगता है कि वे एक कंसलटेंट की मदद लेकर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाएंगे और उसके बाद देश में एक नया झंडा लेकर निकलेंगे. लेकिन, सर्वे में प्रियंका गांधी को सबसे कम मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया गया. मेरा मानना है कि अगर प्रियंका गांधी हिम्मत के साथ कांग्रेस का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में संभालती हैं, तो वह दूसरी पार्टियों के लिए परेशानी अवश्य खड़ी कर देंगी. भले ही उनकी पार्टी को 13 या 23 सीटें मिलें, लेकिन वह बाकी लोगों को, जब तक फ़ैसला नहीं होता, तब तक पसोपेश में डाले रह सकती हैं. वे सारी पार्टियां, जिनमें अजित सिंह, अन्य क्षेत्रीय दल और जदयू शामिल हैं, पांचवें नंबर पर कहां बैठेंगे, कोई नहीं जानता. क्योंकि, आने वाले समय में अभी का जो आधार है, वह ज़्यादा घटेगा-बढ़ेगा नहीं.

इसके बावजूद उत्तर प्रदेश का चुनाव सभी के लिए खुला है. मुलायम सिंह जी को सबसे ज़्यादा चिंतित होना चाहिए. अगर उत्तर प्रदेश उनके हाथ से निकल गया, तो 2019 में बहुत संभावना नहीं है. अब वह 2017 में उत्तर प्रदेश जीतने के लिए रोटी को कितना उलटते-पलटते हैं या अखिलेश यादव को बुलाकर कितना समझाते हैं और अखिलेश उनकी बात को कितना मानते हैं, यह सब भविष्य के गर्भ में है. लेकिन, इतना मानना चाहिए कि मायावती को बढ़त मिली है. इस बढ़त को मनोवैज्ञानिक तौर पर रोकने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी को है. ■

editor@chauthiduniya.com

डोनाल्ड ट्रंप को यूं समझिए

मेघनाद देसाई

डोनाल्ड ट्रंप को समझने में सबने ग़लती की है. वह ऐसे समय में लोकप्रिय हो रहे हैं, जब नहीं होना चाहिए. वह नस्लभेदी हैं, अत्यधिक मुस्लिम विरोधी हैं और हिरासत में यातना का खुला समर्थन करते हैं. जिन महिलाओं ने टीवी पर उनसे सवाल पूछे, ट्रंप ने उन्हें अपमानित किया. तो ऐसे में वह अमेरिकी मतदाताओं की पसंद कैसे बन गए, जबकि उन्हें बहिष्कृत किया जाना चाहिए था? जब लोग किसी राजनेता को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, तो उसके लिए एक घिसा-पिटा शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो उनके हिसाब से बहुत कारगर होता है. वे उसे हिटलर की संज्ञा देते हैं. दरअसल, यह उन लाखों यहूदियों, समलैंगिकों, जिप्सियों, पोलिश, रूसी और अन्य यूरोपीय देशों के नागरिकों का अपमान है, जो हिटलर के हाथों मारे गए थे. इससे पहले नरेंद्र मोदी की भी तुलना हिटलर से की गई, जबकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ ऐसा नहीं हुआ. अब डोनाल्ड ट्रंप की बारी है.

मोदी और ट्रंप के बीच की समानताएं असाधारण हैं. दोनों ने लोगों की यह धारणा ग़लत साबित की कि वे कभी निर्वाचित नहीं हो सकते. मोदी की तरह ट्रंप की पार्टी के लोग भी उन्हें असफल देखना चाहते हैं. गौरतलब है कि भाजपा के अंदर भी ऐसे लोग थे, जो यह भविष्यवाणी कर रहे थे (और यह उनकी इच्छा भी थी) कि पार्टी को 180 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी. वे मोदी को असफल होते देखना चाहते थे. लेकिन अफ़सोस, मोदी ने उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होने दी. ट्रंप एक राज्य के बाद दूसरे राज्य की प्राइमरी जीतते जा रहे हैं और नेशनल ओपिनियन पोल में भी सबसे आगे चल रहे हैं. उन्हें न तो रिपब्लिकन पसंद कर रहे हैं और न डेमोक्रेट्स. इससे यह ज़ाहिर होता है कि आम जनता में स्थापित राजनीति के प्रति खासा असंतोष है. विकसित देशों में अमीर लोगों की तुलना में मध्य वर्ग की आमदनी में गिरावट के ख़िलाफ़ नाराज़गी है. इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (वितरण प्रणाली) के ग्राफ में ऊपर से 10 प्रतिशत को छोड़कर और नीचे से 20 प्रतिशत को छोड़कर शेष 70 प्रतिशत लोगों की आय में स्थिरता आ गई है.

रिपब्लिकन पार्टी पर अमेरिका के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के शीर्ष पांच प्रतिशत अमीरों का क़ब्ज़ा है. उनकी नीतियां अमीरों के लिए अत्यधिक टैक्स कटौती, कल्याणकारी राज्य का प्रभाव कम करने और उद्योगों पर कम से कम नियंत्रण पर केंद्रित रहती हैं. आम आदमी भी उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण पसंद नहीं करता, लेकिन वह अमीरों और उन्हें मिलने वाली रियायतों को भी पसंद नहीं करता. वामपंथ मध्य वर्ग का असंतोष अक्सर समझ नहीं पाता. कम्युनिस्टों के पास इस वर्ग के लिए सर्वहारा अराजक तत्व या पेटिट बुर्जुआ से बेहतर लेबल नहीं है. यह लेबल इस वर्ग को ख़ारिज करने के लिए होता है, लेकिन दक्षिणपंथी राजनेता इस वर्ग के असंतोष को दिशा देना जानते हैं. एक दक्षिणपंथी जनोत्तेजक नेता लोगों के जज्बात भड़काता है, जबकि वामपंथ लोगों के जज्बात उस तरह नहीं भड़काता. दक्षिणपंथी उग्र भाषा का प्रयोग करने से भी परहेज़ नहीं करते, जबकि बर्नी सांडर्स जैसे रेडिकल लेफ्ट नेता भी वैसी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसके अलावा कुछ और भी बिंदु हैं, जो ट्रंप के हक़ में हैं. वर्ष 2008 में विश्व अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हुई, जिसे करदाताओं के पैसों से उबारा गया. उसके बाद बराक ओबामा पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए, बेरोज़गारी बढ़ी और बहुतों को इस मंदी में अपने घरों से भी हाथ धोना पड़ा.

भौंडे नस्लवाद और आर्थिक संकट ने रिपब्लिकन पार्टी के लिए अनुकूल माहौल पैदा किया है. यह राजनीतिक क्रोध, जो अक्सर उग्र रूप धारण कर लेता है, उन लोगों द्वारा ज़ाहिर किया जाता है, जिन्हें वास्तव में आर्थिक नुक़सान उठाना पड़ा है. वे ग़रीब नहीं हैं, लेकिन उन्हें लगातार यह चिंता बनी रहती है कि कहीं वे ग़रीबी में डूब न जाएं. अब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बनने की संभावना बढ़ गई है. लोग यह भूल गए हैं कि रोनाल्ड रीगन जैसे पूर्ववर्ती दक्षिणपंथी नेताओं ने भी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी के दौरान ऐसी ही जज्बाती और भड़काऊ भाषा का प्रयोग किया था. अब अमेरिका के राष्ट्रपतियों में रीगन की रेटिंग बहुत है. तो क्या डोनाल्ड ट्रंप भी हमें आश्चर्यचकित कर सकते हैं? इसका जवाब है, क्यों नहीं? ■

feedback@chauthiduniya.com

कम्प्यूटरीकरण के नाम पर करोड़ों का घोटाला

बिहार दस्तावेज नवीस संघ ने खोला मोर्चा

बिहार दस्तावेज नवीस संघ के अध्यक्ष उदय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारी इन पांच मांगों को मानने में सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं होगा. स्कोर फंड से इन सभी कार्यों को किया जा सकता है. लेकिन निबंधन विभाग हम लोगों के कार्य को ही बाधित करने का प्रयास कर रहा है. निबंधन पदाधिकारियों के काले कारनामों से सरकार को भी अवगत करा रहें हैं. इसलिए दस्तावेज लेखकों को बेरोजगार कर सड़क पर लाने का प्रयास किया जा रहा है.

सुनील सौरभ
feedback@chauthiduniya.com

बिहार में रोजगार के बहुत ही सीमित अवसर हैं. यही कारण है कि बढ़ती आबादी और बढ़ती बेरोजगारी से परेशान युवकों का बिहार से पलायन हो रहा है. राज्य में कहीं भी नए कल-कारखाने नहीं लग पा रहें हैं जो पुराने थे, वह या तो बंद हो गए या खस्ताहाल हैं. अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार की बहुत संभावनाएं नजर नहीं आती हैं जिसके कारण बिहार से दूसरे राज्यों में विशेष कर युवाओं का पलायन जारी है. राज्य सरकार के कुछ विभागों की तरफ से कामों को हाइटेक करने के आदेश दिए गए हैं. अभी राज्य सरकार से लाइसेंस लेकर कुछ लोग यह काम करते रहे हैं. कामों को हाइटेक किए जाने से लाखों को लोग बेराजगार हो जाएंगे.

ऐसा ही मामला बिहार सरकार के निबंधन विभाग का है. विभाग की ओर से जमीन का निबंधन ऑनलाइन किया गया है. इससे सरकार को स्टाम्प शुल्क के रूप में ऑनलाइन पेमेन्ट से निर्धारित राशि तो मिल जाती है. लेकिन स्कोर फंड के रूप में जमीन की खरीद करने वालों से स्कैनिंग के नाम पर जो राशि वसूली जाती है, उससे निबंधन विभाग के कर्मियों की चांदी हो गई है. जबकि दस्तावेज नवीसों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से बेरोजगार होने की संभावना अधिक हो गई है. स्कोर फंड के फंडा को जब दस्तावेज नवीस संघ ने सरकार को बताना शुरू किया तो सरकार से लाइसेंस लेकर कातिब (दस्तावेज लेखक) का काम करने वाले दस्तावेज नवीस निबंधन विभाग के अधिकारियों के आंखो की किरकिरी बन गए. क्योंकि स्कोर फंड की राशि सरकार के खातों में नहीं जाती है और न ही इसके आय-व्यय का ऑडिट होता है. यही कारण है कि निबंधन विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा इस राशि का दुरुपयोग किया जाता है. स्कोर फंड की राशि से ही पिछले वर्ष 2015 के अप्रैल माह में राज्य के करीब तीन दर्जन निबंधन पदाधिकारी गंगटोक घूमने गए थे. इन सब बातों का जब बिहार दस्तावेज संघ के लोगों ने खुलासा करना शुरू किया तो निबंधन विभाग के दस्तावेज नवीसों को ही बेरोजगार करने की साजिश की जा रही है. जबकि दस्तावेज नवीस संघ ने अपने वजूद को कायम रखने के लिए जो पांच सूत्री मांग रखी है, इसमें सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं होना है. लेकिन निबंधन विभाग के पदाधिकारी सरकार को

> **वर्ष 2006 में सरकार ने निर्णय लिया कि सभी निबंधन विभागों को कम्प्यूटरीकृत किया जाए. इसके लिए बहुत विचार-विमर्श किया गया. सरकार ने निर्णय लिया कि कम्प्यूटर लगाने में बहुत अधिक राशि खर्च होगी और उस समय राज्य सरकार की माली हालत भी ठीक नहीं थी. अंत में निर्णय लिया गया कि इसके लिए टेंडर निकाला जाए और निजी कम्पनियों को कम्प्यूटर लगाने का काम दिया जाए.**

उल्टा समझाकर अपने आंखो की किरकिरी बने दस्तावेज नवीसों के पेशा को ही समाप्त कराने में लगे हैं. वहीं बिहार दस्तावेज नवीस संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि पिछले दस साल के स्कोर फंड की जांच कराई जाए तो करोड़ो के घोटाले का मामला सामने आ जाएगा. वर्तमान में बिहार के 38 जिला अवर निबंधन कार्यालय एवं 84 अवर निबंधन कार्यालय को कुल मिलाकर 122 निबंधन कार्यालय कार्यरत हैं. इन सभी निबंधन कार्यालय में 32 हजार लाइसेंसी तथा 10 हजार से अधिक प्रशिक्षु दस्तावेज लेखक का काम कर रहें है. इनके साथ करीब 50 हजार से अधिक सहायक भी काम करने में लगे हैं. यह सभी दस्तावेज नवीस बिहार सरकार के दस्तावेज लेखक अनुज्ञप्ति एक्ट 1996 के तहत लाइसेंस लेकर काम कर रहे हैं. दस्तावेज लेखकों को सरकार की ओर से निर्धारित पारिश्रमिक जमीन का निबंधन कराने वाले की ओर से मिलता है.

वर्ष 2006 में सरकार ने निर्णय लिया कि सभी निबंधन विभागों को कम्प्यूटरीकृत किया जाए. इसके लिए बहुत विचार-विमर्श किया गया. सरकार ने निर्णय लिया कि कम्प्यूटर लगाने में बहुत अधिक राशि खर्च होगी और उस समय राज्य सरकार की माली हालत ठीक नहीं थी. अंत में निर्णय लिया गया कि इसके लिए टेंडर निकाला जाए और निजी कम्पनियों को कम्प्यूटर लगाने का काम दिया जाए. एक कम्पनी को कम्प्यूटर के एक यूनिट के लिए (पांच कम्प्यूटर सेट) प्रति महीने दस हजार रुपये निर्धारित किया गया. कम्प्यूटर लग जाने के बाद सवाल उठा कि इसके ऑपरेटर को पेमेंट कैसे किया जाए? तब दस्तावेज नवीसों के द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों को स्कैनिंग करने के लिए प्रति पेज 25 रुपये निर्धारित किया गया. इस राशि को सभी निबंधन कार्यालय में स्कोर फंड के नाम से रखा जाने लगा. इसी फंड से कम्प्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय तथा कम्प्यूटरों का रख-रखाव किया जाने लगा. करीब एक करोड़ 76 लाख प्रति महीने का भुगतान किया जाता है. इसके भुगतान के नियम के अनुसार निबंधन पदाधिकारी बिल बनाकर जिला पदाधिकारी के यहां भेजते हैं और जिला पदाधिकारी का आदेश आने के बाद निबंधन पदाधिकारी स्कोर फंड से चेक बनाकर भुगतान करते हैं. इस बिल में कम्प्यूटर के रख-रखाव खर्च, प्रिंटर का काटेज, स्टेशनरी तथा अन्य कई तरह के बिल शामिल होते हैं. इसी बिल में घोटाला किया जाता है. एक काटेज की कीमत पांच सौ रुपये से लेकर हजार रुपये होती है, लेकिन इसका बिल 3200 रुपये का बनाया जाता है. इसी प्रकार जो कागज 175 रुपये पैकेट मिलता है, उसका बिल 350 रुपये से लेकर 500 रुपये तक बनाया जाता है. इसी प्रकार कम्प्यूटर के रख-रखाव के नाम पर भी प्रति महीने लाखों रुपये का बिल भुगतान किया जाता है. इसमें बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी होती है. इस कमीशनखोरी में निबंधन कार्यालय से लेकर सचिवालय तक के शामिल होने की बात कही जा रही है. इसके बाद भी स्कोर फंड में जो राशि प्रति महीने जमा होती है, वह खर्च से कई गुना अधिक होती है. सरकार चाहे तो इस राशि से खुद कम्प्यूटर लगाकर प्रति महीने लाखों रुपये का बचत कर सकती है. निबंधन कार्यालय में अन्य तरह के खर्च के नाम पर भी स्कोर फंड से राशि निकालकर खर्च की जाती है.

बिहार दस्तावेज नवीस संघ के अध्यक्ष उदय कुमार सिन्हा तथा महामंत्री मुरारी कुमार सिन्हा ने बताया कि निबंधन पदाधिकारियों के इन्हीं कारनामों से सरकार को अवगत कराने लगे तो दस्तावेज नवीस अधिकारियों के लिए कांटे साबित होने लगे. गया में बिहार दस्तावेज नवीस संघ के चेतावनी रैली में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए हजारों दस्तावेज नवीसों ने अपने कार्य को बाधित करने के खिलाफ एकजुट होकर आर-पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया. संघ ने अपनी पांच सूत्री मांगो में कहा कि दस्तावेज कल्याणकोष की स्थापना की जाए, 16 साल से प्रशिक्षु के रूप में काम कर रहें दस्तावेज लेखकों को लाइसेंस दिया जाए, दस्तावेज लेखकों का पारिश्रमिक का पुनः निर्धारण किया जाए, स्कोर फंड से दस्तावेज लेखकों के बैठने के लिए शेड का निर्माण किया जाए, अनुज्ञप्ति का नवीकरण पांच वर्ष पर किया जाए.

बिहार दस्तावेज नवीस संघ के अध्यक्ष उदय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारी इन पांच मांगों को मानने में सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं होगा. स्कोर फंड से इन सभी कार्यों को किया जा सकता है. लेकिन निबंधन विभाग हम लोगों के कार्य को ही बाधित करने का प्रयास कर रहा है. निबंधन पदाधिकारियों के काले कारनामों से सरकार को भी अवगत करा रहें हैं. इसलिए दस्तावेज लेखकों को बेरोजगार कर सड़क पर लाने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन हम सभी रोटी के सवाल पर संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पूरे बिहार में हमारे कार्य से करीब दस लाख लोग जुड़े हैं. निवीस संघ के गया जिला के महामंत्री अजय शंकर दफतुआर ने कहा कि अपनी जायज मांगों के लिए हम सभी दस्तावेज लेखक एकजुट हैं. संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदय कुमार सिन्हा ने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्कोर फंड की जांच कराई जाए. साथ ही सभी निबंधन पदाधिकारियों की भी संम्पति की जांच करायी जाए, जिससे पता चलेगा कि लाखों लोगों को बेरोजगार करने की साजिश रचने वाले निबंधन विभाग के पदाधिकारी आम लोगों के पैसे का कैसे लूट करते हैं.■

एयरपोर्ट के लिए बंद होगा नेशनल हाइवे

अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल से जुड़ा गया हवाई अड्डा अब देश के व्यस्त हवाईअड्डों में शामिल हो जाएगा. गया हवाईअड्डे को अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाईअड्डा बनाने का प्रयास किया जा रहा है. हिंदू धर्म के लाखों लोग का हर वर्ष अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए गया आते हैं. दुनिया के विभिन्न देशों से बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रद्धालु और पर्यटक भी यहां आते हैं. यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में हर वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है. इसी को देखते हुए गया हवाईअड्डे के विस्तार में अड़ंगा बने नेशनल हाईवे 83 को बंद करने की योजना तैयार कर ली गई है. गया हवाईअड्डे के पूर्वी क्षेत्र में अधिग्रहित की गई करीब तीस एकड़ भूमि के बीच में नेशनल हाइवे आता है. पिछलें दिनों गया एयरपोर्ट के विस्तार के लिए गया के डीएम कुमार रवि ने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को पत्र लिखकर सौ एकड़ भूमि को हस्तगत् करने को कहा है. इसी भूमि के बीच से नेशनल हाइवे 83 गुजरता है. गया एयरपोर्ट के निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि अधिग्रहित जमीन के बीच में सड़क आ रही है जिसकी वजह से विमान लैंडिंग में परेशानी होगी.

संभावना जताई जा रही है कि एयरपोर्ट के निकट नेशनल हाईवे 83 के सड़क को डायवर्ट किया जाएगा या अंडर पास बनाया जा सकता है. एयरपोर्ट विस्तार के लिए सबसे अधिक जमीन हवाईअड्डे के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित विशुनगंज गांव की 70.20 एकड़ जमीन ली जानी है. जिला प्रशासन विशुनगंज के अधिग्रहित जमीन के लिए 13 जुलाई 2012 को ही मुआवजा की राशि 9 करोड़ 54 लाख 15 हजार रुपये सरकारी कोष में जमा कर दिया था. लेकिन विशुनगंज के लोग अधिक राशि देने की मांग कर रहे हैं. हालांकि लीगल एक्स्पर्ट का कहना है कि अधिग्रहित की गई जमीन को ग्रामीण अब देने से इंकार नहीं कर सकते, क्योंकि गया हवाईअड्डे के विस्तार के लिए विशुनगंज की जमीन का अवार्ड नोटीफाई हो चुका है.

गया को नेशनल हाईवे 2 यानि जीटी रोड से जोड़ने वाले एनएच 83 के बंद किए जाने की सूचना पर गया के लोग सवाल करे रहे हैं कि एनएच 83 को कैसे डोभी से जोड़ा जाएगा? क्योंकि डोभी-गया-पटना फोर लेन का निर्माण कार्य शुरू तो हुआ है, लेकिन कार्य बहुत धीमी गति चल रहा है और इसे बनने में दो से तीन वर्ष लग जाएंगे. जबकि गया एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण हो जाने के बाद जल्द काम शुरू हो जाने की संभावना है. पिछले कुछ वर्षों से गया हवाईअड्डे पर बौद्ध देशों से आने वाले विमानों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. वहीं दूसरी ओर गया से सालों भर घरेलू उड़ान की सुविधा उपलब्ध कराने की लगातार मांग की जा रही है. गया हवाईअड्डा परिसर के एप्रन में केवल दो हवाई जहाज की पार्किंग की सुविधा है. इस हवाईअड्डा के रनवे के विस्तार के बाद जहाजों की पार्किंग की सुविधा भी बढ़ जाएगी. भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से मिली जानकारी के अनुसार गया एयरपोर्ट को कोलकाता के नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का स्टैंड बाई एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा. इस वजह से भी गया एयरपोर्ट का जल्द से जल्द विस्तार किया जाना जरूरी था. एयरपोर्ट की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की भी योजना बनाई गई है. एयरपोर्ट पर पुलिस का आउट पोस्ट खोलने का फैसला लिया गया है. क्योंकि पिछले साल होलिका दहन के दौरान एयरपोर्ट परिसर स्थित झाड़ियों में आग लग गई थी. इस आग को बुझाने में लगभग एक सप्ताह लग गया था. साथ ही गया एयरपोर्ट पर विदेशी वस्तुओं एव सोने की तस्करी के मामले भी सामने आ चुके हैं. इन सभी मामले को ध्यान में रखकर गया एयरपोर्ट पर पुलिस का आउटपोस्ट खोलने का निर्णय लिया गया है. हवाईअड्डा के विस्तार के लिए नेशनल हाईवे को बंद किए जाने और अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिलने के सवाल को लेकर लोगों में आक्रोश है.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अडानी समूह पर मेहरबान भाजपा सरकार

प्रशांत शरण

अल्लाह मेहरबान तो... यह कहावत झारखंड के मामले में भी सटीक साबित हो रही है. अडानी समूह पर भाजपा की जो मेहरबानियां बरस रही हैं, वह इसी कहावत को सच साबित कर रही हैं. झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की जब पहली बार बहुमत की सरकार बनी तो इस राज्य के लोगों की उम्मीदें जगीं कि शायद अब झारखंड की सिरत और सूरत में सुधार दिखे, पर इस सरकार के गठन के एक साल हो गए और इस बार भी लोगों को इस सरकार से नाउम्मीदी ही हाथ लग रही है. बहुमत की सरकार बनते ही यहां पर गुजराती उद्योगपतियों की चांदी हो गई है. बड़े-बड़े ठेके से लेकर तमाम उद्योगों पर गुजराती व्यवसायियों का राज होता जा रहा है. खासकर अडानी समूह पर झारखंड सरकार कुछ ज्यादा ही मेहरबान है. बंद पड़े सिंदरी कारखाने का मामला हो या प्रदेश में सोलर प्लांट लगाने की बात हो, इन सभी मामले मे सबसे आगे अडानी घराना है. संथालपरगना में अडानी समूह को उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन दिए जाने को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. जमीन का दाम दस गुना कम कर देने को लेकर विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं. विपक्षी दल पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने को लेकर अड़े हुए हैं. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मामले में अडानी के साथ अरबों रुपये की डील हुई है. विधानसभा में विरोधी दल के नेता एवं पूर्व मूख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कई सवाल खड़े किए हैं. सोरेन ने कहा कि अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए गरीब किसानों का हक मारा जा रहा है.

झारखंड राज्य के मुखिया रघुवर दास सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहते हैं कि राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संथाल परगना में गैरमजरुआ एवं गैरकृषि योग्य जमीन का अधिग्रहण किया गया है. अडानी, जिंदल सहित कई औद्योगिक घरानों ने संथाल परगना में उद्योग लगाने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया था. साथ ही भूमि की भी मांग की थी. औद्योगिक घराने की भूमि की समस्या को देखते हुए इसके निदान के लिए राज्य सरकार ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया था. इसमें कृषि सचिव, उद्योग सचिव, भू-राजस्व सचिव एवं निबंधन सचिव को सदस्य बनाया गया था. कमेटी ने पाया कि संथाल परगना में टेनेंसी एक्ट लागू होने के कारण यहां जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती. लिहाजा, यहां उद्योग एवं अन्य कार्यों के लिए भूमि का न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं हो सकता है. कमेटी ने इसके लिए एक्ट में संशोधन की आवश्यकता बताई. दरअसल, राज्य सरकार ने कमेटी द्वारा निर्धारित की गई दर को कम करने की रणनीति बनाई थी ताकि औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाया जा सके. इसलिए सरकार ने गोड्डा जिले से सटे भागलपुर और बांका जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के दर पर गोड्डा का दर निर्धारण करने को कहा. इन क्षेत्रों में रैयती जमीन की कीमत काफी कम है और इसी को आधार मानते हुए राज्य सरकार ने गोड्डा जिले में जमीन की कीमतें तय कर दीं. पूर्व में गोड्डा जिले के उपायुक्त ने प्रति एकड़ एक करोड़ पांच लाख रुपये दर का निर्धारण किया था, पर सोची-समझी साजिश के तहत जमीन की कीमत राज्य सरकार ने तीन लाख 25 हजार रुपये प्रति एकड़ तय कर दी जबकि इससे पूर्व गोड्डा के उपायुक्त ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के आलोक में पहले ही दर कम कर 41 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दी थी.

गौतम अडानी

रघुवर दास

राज्य सरकार ने जमीन की कीमत कम करने के पीछे दलील दी है कि पूर्व में जमीन की कीमत बहुत अधिक थी. राज्य के रियाडा, वियाडा और आयडा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में संथाल परगना की दर बहुत अधिक थी. जमशेदपुर के आदित्यपुर में जमीन की कीमत 15 लाख 19 हजार रुपये प्रति एकड़ थी, जबकि बोकारो में दस लाख रुपये प्रति एकड़. संथाल परगना में ज्यादा कीमत रहने के कारण औद्योगिक एवं पर्यटन विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था. पर, वास्तविकता इससे कहीं अलग है. अडानी समूह को गोड्डा में पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 2000 एकड़ जमीन की आवश्यकता है. अडानी समूह ने यहां एक हजार मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने की भी इच्छा जताई है, साथ ही इस समूह की नजर सिंदरी में बंद पड़े खाद कारखाना पर भी है.

लोगों में इस बात की चर्चा है कि अडानी समूह के मुखिया के साथ भाजपा सुप्रीमो अमित शाह एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मधुर संबंध हैं, और इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश में यह समूह लगा हुआ है. झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी भाजपा सुप्रीमो के काफी नजदीक माने जाते हैं और उनके विश्वासपात्र नेताओं में से एक हैं. जाहिर है, ऐसे में अमित शाह के मित्र आडानी को वे कैसे नाराज कर सकते हैं. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस जमीन को लेकर एक बड़ी डील हुई है. बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से झारखंड मुद्रांक नियमावली 2009 और 2012 में संशोधन किया गया है. इसके तहत गोड्डा जिले की जमीन का मूल्य 10 नवम्बर 2015 से दो वर्षों के लिए घटाकर तीन लाख 25 हजार रुपये प्रति एकड़ निर्धारित कर दिया गया है, इससे किसानों को कम मुआवजा मिलेगा. मरांडी ने कहा कि उनकी पार्टी इसे लेकर आंदोलन करेगी साथ ही अडानी समूह को यहां उद्योग स्थापित नहीं करने देगी.

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में विरोधी दल के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों का हित मारा जा रहा है. पर जब सरकार ही मेहरबान हो तो कोई औद्योगिक घराना अपने को पहलवान समझेगा ही. उद्योगपति अडानी भी खुद को पहलवान समझ कर झारखंड में अपना पांव फैलाने की तैयारी कर चुके हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

स्वास्थ्य विभाग में फ़र्ज़ीवाड़ा!

सुरेश चौहान

बिहार के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है. पैरवी एवं पैसे के बल पर फर्जीवाड़े का बाज़ार गर्म है. विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी नियुक्ति एवं फर्जी स्थानांतरण का मामला उजागर होने के बावजूद कर्मी बेफिक्र कार्यरत हैं. फर्जी नियुक्ति को अंजाम देने वाले विभागीय पदाधिकारियों के चलते उक्त कर्मियों की सेवा पुस्तिका भी बना दी गई. सच्चाई सबके सामने न आ जाए, इससे बचने के लिए उक्त कर्मी फर्जी स्थानांतरण पत्र के आधार पर तबादला कराते रहे. प्रमुख निदेशक-स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा उक्त कर्मियों की सेवा समाप्त करने के लिए विभागीय कार्रवाई का आदेश निर्गत किया. इसके बावजूद आज तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई.

फर्जी नियुक्ति एवं स्थानांतरण का मामला सिविल सर्जन कार्यालय बेगूसराय में कार्यरत लिपिक शिव नंदन महतो एवं नंद किशोर पंडित से संबंधित है. शिव नंदन की नियुक्ति सिविल सर्जन मधुबनी के फर्जी नियुक्ति पत्रांक 1179 दिनांक 29.06.1987 के आधार पर मधुबनी ज़िले के लदनियां पीएचसी में की गई. 1977 से 1989 तक वह लदनियां पीएचसी में लिपिक पद पर कार्यरत रहा. फिर उसने अपना तबादला क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, दरभंगा प्रमंडल कार्यालय, बेगूसराय करा लिया. इसी दौरान डॉ. अरविंद प्रसाद सिंह, ग्राम हर्रख, पोस्ट-ज़िला बेगूसराय द्वारा ज़िला पदाधिकारी को आवेदन दिया गया कि शिवनंदन महतो की नियुक्ति फर्जी है. ज़िला पदाधिकारी ने वरीय कोषागार पदाधिकारी द्वारा जांच कराई. जांच में पाया गया कि शिवनंदन महतो के नियुक्ति एवं स्थानांतरण पत्र फर्जी हैं. इसी तरह नंद किशोर पंडित ने सिविल सर्जन, मधुबनी के फर्जी नियुक्ति पत्रांक 1575 दिनांक 05.08.1987 के आधार पर मधेपुर पीएचसी में लिपिक का पद ग्रहण किया और उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, दरभंगा प्रमंडल के फर्जी स्थानांतरण पत्रांक 29 दिनांक 18.01.1989 द्वारा अपना तबादला बेगूसराय सिविल सर्जन कार्यालय में करा लिया. डॉ. अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि नंद किशोर पंडित की नियुक्ति फर्जी है. ज़िला पदाधिकारी ने कोषागर पदाधिकारी द्वारा मामले की सघन जांच कराई. कोषागार पदाधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में कहा कि लिपिक नंद किशोर पंडित के नियुक्ति और स्थानांतरण पत्र फर्जी हैं. ज़िला पदाधिकारी ने प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को जांच प्रतिवेदन भेजते हुए अनुरोध किया कि शिव नंदन महतो और नंद किशोर पंडित की नियुक्तियां फर्जी हैं, जिन्हें भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए सेवामुक्त किया जाए. बावजूद इसके नंद किशोर पंडित और शिव नंदन आज तक अपने पद पर कार्यरत हैं.

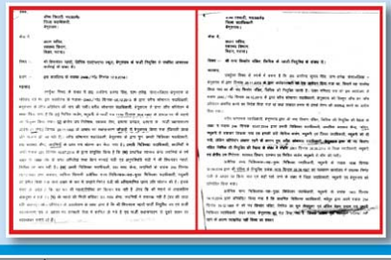

उक्त कर्मी 28 वर्षों से कोषागार से वेतन प्राप्त करते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला कराते रहे, लेकिन विभागीय पदाधिकारी सोते रहे. नियुक्ति और सेवा पुस्तिका बनाते समय नियुक्ति पत्र की जांच क्यों नहीं कराई गई? क्या कर्मियों के साथ दोषी पाए गए विभागीय पदाधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी? अगर स्वास्थ्य मंत्री उच्चस्तरीय जांच कराएं, तो फर्जी नियुक्तियों के और भी मामले उजागर हो सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आर्युवेदिक दवा बतायें । दीनानाथ सिंह, रांची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कौप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते सम लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मै क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मिता विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए । मैं क्या करूं? शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिशन में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ. साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।

प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कम पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें : REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटरः दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुरः आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसरायः प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छतीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहारः मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेर्डस 9903175579, देव मार्केटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंडः सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलवर्गा:9343834519

बांझपन कारण और निदान

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

DR.(MRS.)SHAZIA KHAN
(MD)Gynecologist, PURNEA

पूर्णिया में के. नगर की डॉ. शाजिया खान (गायनोकॉलोजिस्ट) अपने इन्टरव्यू के दौरान महिलाओं को उनके पिरियड में होने वाली प्रॉब्लम के प्रति सजग रहने को कहा और थोड़ी सी परेशानी रहने पर किसी कुशल ग्यानोकॉलॉजिस्ट से मिलने की बात की। बांझपन पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बांझपन एक ऐसा श्राप है जिसके कारण महिलाओं को मानसिक रूप से भी याताना झेलनी पड़ती है। इसलिए इस श्राप से मुक्त रहना है तो महिलाओं को कुंवारेपन से ही मासिक/पीरियड के प्रति सजग हो जाना चाहिए। यदि मासिक समय पर नहीं हो रहा हो **या** पहले हो रहा हो **या** फिर काफी पेनपुल हो तो तुंरत ग्यानोकॉलोजिस्ट से सम्पर्क करें। बांझपन के कारणों में मासिक धर्म के अलावे ट्यूब नली का बन्द होना, अंडा का नहीं बन पाना या फिर स्ट्रक्चरल समस्या को बताया। यदि साधारण कारण है तो एच.एस. जी. से उसका निदान कर देते हैं । लेकिन इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो किसी अच्छे सुपरस्पेशलियटि अस्पताल में इलाज होता है।यह पेन के आकार का होता है जिसका इलाज बड़े अस्पतालों में ही अच्छे से संभव है। ओवरी में अंडे 10 से 15 साल में बनने शुरू हो जाते हैं यही अंडे बड़ा होकर फूटता है और महावरी होती है। जब अंडा खत्म हो जाता है तो महावारी बन्द हो जाती है। कई मामलों में यदि औरतों में टीवी रोग हो तो वह भी बांझपन का कारण बनती है। बॉडी में हारमोन, थायराइड, टेस्टीरोन आदि का इनबैलेन्स भी बांझपन का कारण बनती है। ■ -भारती

URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap
Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

एक फोन कॉल पर खड़ी होगी पुलिस आपके द्वार

काफी समय से पुलिस में वाहनों की कमी महसूस की जा रही थी, जिसके मद्देनजर पिछले दिनों अपने सरकारी आवास में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृहद कार्यक्रम में लगभग 54 करोड़ रु. की लागत के 1056 नये चार-पहिया पुलिस वाहनों को पुलिस को सौंपा। पहली बार किसी सरकार द्वारा एक साथ इतनी संख्या में चार-पहिया वाहन पुलिस विभाग को उपलब्ध कराये गये। बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए डायल '100' योजना के संचालन के लिए उपलब्ध कराये गये ये वाहन '102' एवं '108' एम्बुलेंस की तर्ज पर पुलिस मौके पर 15 से 20 मिनट में पहुंचने में सफल होगी। पुलिस को ऐसा माहौल बनाये रखने की आवश्यकता है, जिसमें जनता राहत महसूस करें जबकि अपराधी भयभीत रहें। पुलिसकर्मियों की जरूरत के अनुसार उनकी सेवा शर्तों एवं बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया गया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए तत्पर हैं और उन्होंने डायल '100' योजना संचालन हेतु लगभग 54 करोड़ रुपये की लागत के 1056 नये चार-पहिया वाहनों को पुलिस विभाग को बेहतर कानून व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराया। इन वाहनों के प्राप्त होने से 1,000 थानों पर पुलिस को अब 02-02 वाहन उपल्ब्ध हो जाएंगे।

पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा इतनी संख्या में एक साथ चार-पहिया वाहन पुलिस विभाग को उपलब्ध कराये गये हैं। इससे जहां पुलिसकर्मियों की गतिशीलता में बढोत्तरी होगी वहीं जनता में और अधिक सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। श्री यादव को भरोसा है कि डायल '100' नम्बर की केन्द्रीयकृत प्रणाली स्थापित हो जाने पर पुलिस, समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के तहत संचालित '102' एवं '108' एम्बुलेंस की तर्ज पर आवश्यकतानुसार मौके पर 15 से 20 मिनट में पहुंचने में सफल होगी। इसके लिए पुलिस को जरूरी संसाधन मुहैया कराया जा रहा है। आज भी पुलिस का इकबाल कायम है और इसकी वर्दी को सम्मान से देखा जाता है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस को ऐसा माहौल लगातार बनाये रखने की आवश्यकता है, जिसमें जनता राहत महसूस करें जबकि अपराधी भयभीत रहें।

श्री यादव का मानना है कि पुलिस के अच्छे कार्यों की निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिए। वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस विभाग को

आवश्यकतानुसार संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कई बड़े फैसले कर रही है। हर स्तर पर महकमे के कर्मचारियों को पदोन्नति दी गयी है। पुलिस को आधुनिक संचार सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विमेन पावरलाइन '1090' को सफलतापूर्वक लागू किया गया, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं को राहत पहुंचाई गयी। इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद केवल संसाधनों की बदौलत प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक कर पाना सम्भव नहीं था। इसलिए पुलिस विभाग के सबसे निचले स्तर पर तैनात आरक्षी तक को उनकी जरूरतों के अनुसार सेवा शर्तों को बेहतर बनाते हुए सुविधा देने का प्रयास किया गया। थानों की दशा को सुधारने तथा आधुनिक परिस्थितियों में जरूरत के हिसाब से नये थानों तथा बैरकों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। पुलिसकर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था जैसे जरूरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण काम किये जा रहे हैं। इसके साथ ही आधुनिक नियंत्रण कक्षों की स्थापना, नगरों की यातायात व्यवस्था सुधारने तथा भीड़ पर निगाह रखने के लिए आधुनिक संसाधनों की व्यवस्था का कार्य भी लगातार किया जा रहा है।

वर्तमान राज्य सरकार से पूर्व महिलाओं को गलत तथा अवांछित फोन, एस.एस.एस., एम.एम.एस. आदि से बचाने की व्यवस्था नहीं की गयी थी। इन तमाम समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ही राज्य सरकार विमेन पावर लाइन '1090' की शुरुआत की, जिसकी नकल अब देश-विदेश की तमाम महत्वपूर्ण सरकारें कर रहीं हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाये हैं। पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली के विषय में युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का मानना है कि पुलिस को विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। प्रदेश पुलिस के कार्यों की तुलना दुनिया के बेहतरीन पुलिस विभागों से करने से पूर्व इस तथ्य पर भी विचार किया जाना चाहिए कि प्रदेश पुलिस को क्या सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। मुख्यमंत्री को भरोसा है कि वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों के चलते जैसे-जैसे पुलिसकर्मियों के कार्य निष्पादन की परिस्थितियों में सुधार होता जाएगा वैसे-वैसे पुलिस की कार्यप्रणाली में भी सुधार आएगा। श्री यादव को विश्वास है कि विकास के मामले में समाजवादी सरकार से किसी अन्य राज्य सरकार की तुलना नहीं की जा सकती। राज्य सरकार अपने संसाधनों से जिस पैमाने पर गांव एवं शहरों के विकास के लिए काम कर रही है, इतने बड़े पैमाने पर किसी अन्य सरकारों द्वारा कभी नहीं कियागया। उत्तर प्रदेश एक बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। मुख्यमंत्री पूरी संवेदनशीलता से राज्य की कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा अपराध पर प्रभावी नियंत्रण कायम रखने के लिए पुलिस विभाग को लगातार प्रेरित करते रहे हैं और इसके लिए जरूरी संसाधन भी प्राथमिकता पर उपलब्ध कराते रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रयासों के चलते ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के कई राज्यों से काफी बेहतर है। पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण के लिए किये जा रहे प्रयासों की हर ओ सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री ने पुलिस का मानवीय चेहरा जनता के सामने लाने का महत्वपूर्ण काम किया है। मुख्यमंत्री श्री यादव तत्काल निर्णय लेते हुए हर असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। जो वाहन पुलिस विभाग को दिये गये हैं। इन्हें 1000 थानों में तैनात किया जाएगा। इसके अलावा द्वितीय चरण में 37 करोड़ रुपये की लागत से 526 चार-पहिया वाहनों को शेष थानों को प्रदान किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के सभी थानों में 02-02 वाहन उपलब्ध हो जाएंगे।

हाईटेक तकनीक के साथ बदल रही है
उत्तर प्रदेश पुलिस

पुलिस को प्रभावी बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने तथा बेहतर प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जब यह कहते हैं तो उनका अभिप्राय आधुनिक संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा देकर प्रदेश की पुलिस का रिस्पांस टाइम कम कर उत्कृष्ट पुलिस सुरक्षा प्रदेश के प्रत्येक आदमी तक पहुंचाना है। इस सोच को बदलते परिवेश से जोड़ते हुए युवा मुख्यमंत्री ने प्रदेश को 'खोई वस्तु रिपोर्ट सेवा' 'तत्पर', 'सोशल मीडिया लैब' 'दृष्टि', 'सम्मान', तथा 'उन्नयन' योजनाओं का तोहफा भी दिया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव राज्य की पुलिस को प्रभावी एवं सक्षम बनाने के लिए सूचना तकनीक सहित अन्य आधुनिक संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा देकर प्रदेश की पुलिस का रिस्पांस टाइम '108' समाजवादी स्वास्थ्य सेवा की तरह कम करना चाहते हैं। उनका मानना है कि जन सुरक्षा हेतु प्रदेश पुलिस की नई योजनाओं का सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिले और लोगों को अनावश्यक थानों का चक्कर काटने से राहत मिले।

जन-सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस की नई जनकेन्द्रित योजनाएं जैसे 'खोई वस्तु रिपोर्ट सेवा', 'तत्पर', 'सोशाल मीडिया लैब', 'दृष्टि', 'सम्मान' तथा 'उन्नयन' तकनीक आधारित हैं। इससे ग्रामीण एवं शहरी जनता को निश्चित रूप से मदद मिलेगी और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थापित थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों की कार्य प्रणाली पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आसानी से निगाह रखी जा सकेगी।

श्री यादव कहते हैं कि बदलते हुए परिवेश में अपराध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। इन अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस को अपनी कार्य प्रणाली में लगातार बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए कई कदम उठाये हैं और भविष्य में भी आवश्यकतानुसार निर्णय लिये जाते रहेंगे। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बताते हुए कहा कि तथाकथित बेहतर कानून व्यवस्था वाले प्रदेशों की कानून व्यवस्था काफी खराब हालत में है। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस द्वारा अपनी कार्यशैली में सुधार एवं आवश्यक जरूरतों के लिए बनायी गयी योजनाओं की तारीफ देश-विदेश के उद्योग घरानों द्वारा भी की जा रही है और यही कारण है कि आज प्रमुख औद्योगिक निवेश उत्तर प्रदेश में आने को तत्पर हैं। राज्य सरकार द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद कानपुर का आधुनिक पुलिस कन्ट्रोल रूम निर्धारित समय से पहले पूरा हो गया। इसी प्रकार लखनऊ का आधुनिक पुलिस कन्ट्रोल रूम भी समय से पहले कार्य करने लगा है। इसका असर प्रदेश के अन्य जनपदों में पड़ा, जहां अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर पहल करके सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित कराने तथा नियंत्रण कक्ष को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का काम किया है। बदलते वक्त के अनुसार प्रदेश पुलिस की कार्यशैली में आ रहे परिवर्तन की सराहना देश-विदेश में भी हो रही है। 'खोई वस्तु रिपोर्ट सेवा' योजना के तहत लोग अपने मोबाइल या नेट के माध्यम से पासपोर्ट, मोबाइल एवं अन्य अभिलेखों के खो जाने पर थाने जाने के बजाए घर बैठे रिपोर्ट लिखाकर डिजीटल हस्ताक्षरित पावती प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार 'तत्पर' योजना के माध्यम से मात्र एक बटन दबाकर रजिस्टर्ड संस्थाएं आस-पास के तीन थानों की मदद प्राप्त कर सकेंगी। भविष्य में सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने लिए 'सोशल मीडिया लैब' परियोजना के तहत लखनऊ के 70 चौराहों पर 280 कैमरे लगाये जा रहे हैं।

इसी प्रकार 'सम्मान' योजना के तहत प्रदेश के जी.आर.पी. थानों सहित सभी थानों में 2-2 सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किये जा रहे हैं। पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद लखनऊ के गाजीपुर, हजरतगंज, महानगर तथा नाका थानों में कैमरे स्थापित किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 'उन्नयन' योजना के तहत थानों के वर्तमान स्वरूप को आधुनिक बनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रथम चरण में लखनऊ के चौक, हुसैनगंज एवं गाजीपुर थानों का उन्नयन किया जाएगा।

महिलाओं के लिए पुलिस का 1090 मोबाइल एप शुरू

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के मौके पर श्री यादव ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को कई तोहफे दिये। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश पुलिस का अनोखा '1090 एप', 11 जिलों में आशा ज्योति योजना और लखनऊ में आधुनिक पुलिस कन्ट्रोल रूम भी शुरू हो चुका है। **आपात स्थिति में मददगार :** 1090 एप महिलाओं को अपने एंड्रायड मोबाइल फोन पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। आपात स्थिति में इसका बटन क्लिक करते ही मदद के लिए सीधे कंट्रोल रूम व संबंधित थाने की पुलिस को मैसेज जाएगा। 11 जिलों में **आशा ज्योति केन्द्र :** मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आगरा, बरेली, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर और वाराणसी समेत 11 जिलों में आशा ज्योति केन्द्र शुरू करने की भी योजना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं व बेटियों के लिए इसे बड़ा कदम करार दिया है। इसमें महिला सुरक्षा (1090), चाइल्ड हेल्प लाइन (1098) व एम्बुलेन्स सेवा -108 एक साथ काम करेंगी।मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की शिकायत ऑनलाइन दर्ज किये जाने की व्यवस्था पूरी तरह लागू कर दी गयी। सूबे में पहली बार महिला उत्पीड़न की शिकायतों के प्रति पुलिस को संवेदनशील व जवाबदेह बनाने के लिए वीमेन हेल्प लाइन 1090 के बाद यह प्रयोग किया गया है। पूरे देश में अपने आप में अनूठी इस सुविधा में अब महिलाओं को थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज नहीं करनी होगी। वे घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

महिलाओं की एफआईआर भी अब होगी आनलाइन दर्ज

सीएम भी देख सकेंगे कार्यवाही हुई या नहीं

ऑनलाइन होने के कारण शिकायत पर हुई कार्यवाही की जानकारी पर मुख्यमंत्री समीक्षा भी कर सकते हैं। शिकायत के बाद हुई प्रगति समीक्षा भी सीएम स्वयं देख सकते हैं।

पुलिस को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील उ.प्र. सरकार

खुशियों भरा है अपना ये जहान

अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक हालात में लाभकारी बदलाव

भारत के संविधान में देश को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र घोषित किया गया है। संविधान जहां देश के नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, वहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार भी प्रदान करता है। साथ ही उन्हें अपनी पसन्द की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रबन्धन का भी अधिकार देता है।

अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने एवं उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं। ऐसी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, संचालन एवं समन्वय के लिए अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने कई ऐसी बातों पर विशेष रूप से गौर किया है, जिनके द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक स्थिति में लाभकारी परिवर्तन कर और बेहतर बनाने में सहायक मिलेगी।

सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों में स्कूल छोड़ देने (ड्राप-आउट) की प्रवृत्ति नियंत्रित करने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के समान छात्रवृत्ति वितरित कर शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण कर उनमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी का पठन-पाठन भी कराया जा रहा है। ताकि इनसे पढ़कर निकले अल्पसंख्यक छात्र/छात्राएं कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के हर क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से सहभागिता कर सकें। मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, जिससे कि इन परम्परागत शिक्षण संस्थाओं से शिक्षण प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सके। शैक्षिक रूप से पिछड़े कई अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावासों हु। निर्माण किया जा रहा है।

वक्फ सम्पत्तियों का विकास कर उनसे होने वाली आय को इस प्रकार बढ़ाया जा रहा है ताकि वक्फ वाकिफ की इच्छानुसार परोपकारी (सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक) संस्थाओं के रूप में प्रभावी योगदान कर सकें।

मातृ/शिशु तथा वृद्धों से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की अल्पसंख्यकों में पहुंच बढ़ायी गयी है, जिसके सुखद परिणाम प्राप्त हुए हैं। निजी/अर्द्ध सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की सेवा योजन की स्थिति में सुधार हेतु चलायी जा रही योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करने के लिए अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं संचालित शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्रदान किया गया है।

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वरोजगार हेतु ऋण दिलाने के लिए मार्जिन मनी उपलब्ध कराना, टर्मलोन देना तथा मेधावी छात्रों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याजरहित ऋण उपलब्ध कराना तथा राज्य के विभिन्न विभागों के माध्यम से चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर्याप्त रूप से बनी रहे एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्यान्वयन में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों तथा राज्य सरकार की मंशा का पूर्ण रूप से समावेश होता रहे, इस आशय से यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों की राज्य स्तरीय समितियों, जो योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए गठित की गयी हो, में सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। इसी प्रकार जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित समितियों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा।

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं

निर्धन/निराश्रित अभिभावकों की पुत्री के विवाह के लिए अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की दो पुत्रियों के विवाह के लिए रु. 10,000/-प्रत्येक के आधार पर आगामी 06 माह के अन्दर प्रस्तावित अथवा गत् 06 माह के अन्दर सम्पन्न विवाह आयोजन के लिए रु. 10,000/- की सहायता दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना

अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों/युवतियों को स्वावलम्बी बनाने तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सरकारी तथा गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से यह योजना चलायी जा रही है। जिसमें इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर, टाइपिंग, वेल्डिंग, मोटर ड्राइविंग, फोटोग्राफी, आटोमोबाइल्स,रैफ्रीजेटर, एयरकण्डीशनिंग एवं फैशन डिजाइनिंग आदि अनेक उपयोगी व्यवसायों से अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को निगम के टर्मलोन/मार्जिन मनी, ऋण योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान कर उन्हें स्वतः रोजगार में स्थापित करने का प्रयास भी किया जा रहा है।

शिक्षा के बिना किसी भी समुदाय के उत्थान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस तथ्य को समझते हुए उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा अन्य सहूलियतें प्रदानर करने के उद्देश्य से कई योजनाएं चलायी हैं, ताकि अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर भविष्य निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें।

पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा-1 से 10 तक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत समुदाय के ऐसे सभी छात्रों, जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रु. 1.00 लाख है, योजनान्तर्गत अर्ह/पात्र माने जाएंगे तथा उन्हें मासिक/वार्षिक दरों पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति वितरण में और अधिक पारदर्शिता लाये जाने एवं लाभार्थी को त्वरित भुगतान के उद्देश्य से पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण बैंक खाते के माध्यम से करने की व्यवस्था दी गयी है तथा जनपद स्तर पर परिलक्षित मांग के आधार पर धनराशि का अन्तरण/वितरण सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते के माध्यम से किया जा रहा है।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रु. 2.00 लाख तक है, योजनाअन्तर्गत अर्ह/पात्र माने जाएंगे तथा उन्हें मासिक दरों पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत भी पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की धनराशि का अन्तरण सीधे उनके बैंक खातों में किये जाने का प्राविधान है जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी परिलक्षित मांग के आधार पर धनराशि का अन्तरण पात्र छात्र/छात्राओं के खाते में बैंक एडवाइस के माध्यम से किया जाता है।

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत समुदाय के ऐसे सभी छात्रों जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रु., 2.00 लाख है, को राजकीय संस्थानों के लिए निर्धारित शुल्क की देय धनराशि छात्र/छात्राओं के खाते में बैंक खातों में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

लखनऊ में आई.ए.एस., पी.सी.एस. कोचिंग संस्थान भी अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। जनपद लखनऊ में 300 छात्र/छात्राओं के लिए एक आई.ए.एस./पी.सी.एस. कोचिंग केन्द्र जनपद लखनऊ में मोहान रोड पर ग्राम पारा में निर्माणाधीन है। प्रथम चरण में 150 अभ्यर्थियों से प्रारम्भ किये जाने की योजना है।

अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्र/छात्राओं के कल्याणार्थ मेडिकल/इंजीनियरिंग की परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में 100 छात्र/छात्राओं को मेडिकल/इंजीनियरिंग की कोचिंग योजना के लिए कुल फीस (अधिकतम रु. 15000/- प्रति अभ्यर्थी) दी जाती है। अभ्यर्थी को कोचिंग में प्रवेश के समय 50 प्रतिशत राशि एवं कोर्स समाप्ति पर 50 प्रतिशत की धनराशि एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से दी जाती है।

हर कदम पर साथ.... समाजवादी सरकार

अरबी-फारसी मदरसे संवारेंगे नौनिहालों का भविष्य

अरबी फारसी मदरसों को मान्यता प्रदान करने तथा इनकी परीक्षाओं को संचालित करने हेतु प्रदेश स्तर पर अरबी-फारसी मदरसा बोर्ड स्थापित है। निरीक्षक, अरबी फारसी मदरसा ही बोर्ड के पदेन रजिस्ट्रार भी होते हैं।

पूर्व में प्रदेश के तहतानियां, फौकानियां तथा उच्च श्रेणी के मदरसों को मान्यता रजिस्ट्रार स्तर से प्रदान की जाती थी। शासन द्वारा एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी निर्णय लेकर तहतानियं, फौकानिया स्तर तक की मान्यता का अधिकार जनपद स्तर पर दे दिया गया है।

मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए शासन द्वारा उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए समय-समय पर आलिया स्तर के मान्यताप्राप्त अरबी फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में कई अरबी फारसी मदरसों को शासकीय अनुदान दिया जा रहा है। वेतन का भुगतान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से किया जाता है।

अनुदानियों मदरसों के सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के लिए पेंशन की योजना संचालित की जा रही है। मदरसों का कार्य शिक्षा विभाग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को स्थानान्तरित किये जाने के बाद पेंशन की स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। स्वीकृति की प्रक्रिया में आ रही कतिपय कठिनाइयों के निराकरण के लिए नियमों में संशोधन किया गया है।

अरबी फारसी मदरसों के समुचित उन्नयन एवं विकास के लिए अरबी फारसी मदरसा विकास निधि की स्थापना की गयी है। निधि का सृजन राज्य की संचित निधि से किया गया है। शासकीय अनुदान के अतिरिक्त प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित किसी अन्य स्रोतों से भी निधि के आकार को बढ़ाने के लिए अनुदान, दान, संदान या अन्य अंशदान स्वीकार किया जा सकेगा।

निधि का उद्देश्य अरबी फारसी मदरसों में संचालित पाठ्य पुस्तकों के लेखन में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया धाना, उच्च शिक्षा स्तर तक के विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए अनुदान देना, मदरसा शिक्षा के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहयोग देना, अच्छी ख्याति के मदरसों में मैचिंग बेसिस पर कम्प्यूटर उपलब्ध कराना, अरबी-फारसी शिक्षा के विकास से सम्बन्धित अन्य कार्य इत्यादि है। निधि के उपरोक्त उद्देश्यों के अन्तर्गत वही मदरसे/छात्र/शिक्षाविद् आर्थिक सहायता/प्रोत्साहन इत्यादि के लिए पात्र होंगे जिन्हें उसी प्रयोजनार्थ अन्य स्रोतों से सहायता/प्रोत्साहन उपलब्ध न हो।

अनुदानित मदरसों को पोषण अनुदान दिये जाने की योजना के अन्तर्गत अनुदानित मदरसों में विद्युत व्यय, जल/भूमिकर, पुस्तक एवं लेखन सामग्री, काण्टोपकरण, संयोगिक व्यय तथा भवन के जीर्णोद्धार के लिए निर्धारित शर्तों एवं मानक के अनुसार अनुदान दिया जाता है।

कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूरा होने को

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार अपने वादे के अनुसार कब्रिस्तानों की चहारदीवारी/अन्त्येष्टि स्थलों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने व भूमि की सुरक्षा के लिए चहारदीवारी का निर्माण व सुदृढ़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। कब्रिस्तानी/अन्त्येष्टि स्थलों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराने हेतु लगभग 200 करोड़ रुपये के स्पेशल पैकेज की व्यवस्था की थ्री है। यह धनराशि जिलाधिकारियों के माध्यम से निर्माण के लिए उपलब्ध करायी जाएगी। इस प्रक्रिया में जिलाधिकारी जिलों में स्थित कब्रिस्तानों की चहारदीवारी के निर्माण के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, शिया/सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव पर बाउण्ड्रीवाल निर्माण के लिए स्वीकृति निर्गत कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को भेजते हैं। कब्रिस्तानों की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिलाधिकारी/अपर सर्वेक्षण आयुक्त, वक्फ की अध्यक्षता में चयन समिति गठित कर निर्माण कार्य हो रहा है। राज्य की समाजवादी सरकार का यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बेहतर अवसर एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यावसायिक कोर्सों तथा नौकरियों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस वर्ग के प्रतियोगियों को तैयार करने के लिए निगम द्वारा कोचिंग योजना चलायी जा रही है। योजना के लिए वही अभ्यर्थी पात्र हैं, जिनके अभिभावकों की आय एक लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव उर्दू आई.ए.एस. स्टडी सेण्टर

शिक्षा के बिना कोई देश या समाज तरक्की नहीं कर सकता है। विश्व में विकसित कहे जाने वाले राष्ट्रों ने सबसे पहले अपने देश के किसानों की खुशहाली एवं शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया, तभी वे आज आर्थिक तरक्की के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उर्दू भाषा के माध्यम से देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षा का सपना देखने वाले नौजवानों के लिए रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव उर्दू आई.ए.एस. स्टडी सेण्टर में हर सम्भव सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का बजट दोगुना करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाली वर्तमान राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका प्रदान कर रही है। धर्म निरपेक्षता के मार्ग पर चलकर ही देश को विकसित किया जा सकता है। देश में परिवर्तन तभी आएगा जब सभी को प्रगति का पर्याप्त अवसर मिले।

स्टडी सेण्टर की स्थापना के लिए उर्दू अकादमी की ओर से विशेष प्रयास किये गये हैं। इससे नौजवानों को अपने भविष्य को संवारने का बेहतर विकल्प मिलेगा। आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव हमेशा समाज के सभी वर्गों की भलाई पर जोर देते हैं, उनके नाम पर स्थापित हो रहे इस सेण्टर से उनके सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत करने का मौका मिलेगा। इस सेण्टर के कायम होने से उर्दू भाषा को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे उर्दू भाषा के साथ अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में बैठने वाले नौजवानों को राहत मिलेगी। आई.ए.एस. जैसी परीक्षा के लिए क्रमबद्ध तैयारी एवं बेहतर मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। स्टडी सेण्टर की स्थापना से उर्दू भाषा के साथ आई.ए.एस. की परीक्षा में भाग्य आजमाने वाले नौजवानों को सुविधा मिलेगी।

इस सेण्टर के लिए नौजवानों का चयन करते समय विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि शैक्षिक रूप से योग्य नौजवान ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। नौजवानों को हमेशा बड़ा सपना देखना चाहिए और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए।

आधार बिल पर बहस : संसद में फिर लहराया चौथी दुनिया

संसद में एक बार फिर चौथी दुनिया अख़बार लहराया. इस बार जनता दल यूनाइटेड के सांसद केसी त्यागी ने राज्यसभा में आधार कार्ड बिल-2016 पर हो रही बहस के दौरान चौथी दुनिया की प्रतियां लहराईं. उन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान आधार कार्ड को लेकर चौथी दुनिया में छपी विस्तृत रिपोर्टों का हवाला देते हुए इस कार्ड से जुड़े ख़तरों से सदन को अवगत कराया. त्यागी ने चौथी दुनिया में प्रकाशित क़रीब आधा दर्जन ख़बरों की हेडलाइन दोहराते हुए सुरक्षा को लेकर सारी आशंकाएं सदन के सामने रखीं. चौथी दुनिया आधार कार्ड के ख़तरों और गोरखधंधों को लगातार उजागर करता आया है. अख़बार अपने पाठकों को बताता रहा है कि आधार कार्ड को वैधता प्रदान करने वाले बिल के संसद में लंबित होने के बावजूद यूपीए-2 सरकार सारे नियम-क़ानून ताक पर रखकर पिछले दरवाजे से इसे कैसे लागू कराती रही और तब विपक्ष में बैठी भाजपा कैसे विरोध करती रही व सत्ता में आने के बाद पुनर्विचार की बात कहती रही. संसद में केसी त्यागी ने चौथी दुनिया के अंक दिखाने से ही अपनी बात शुरू की और अख़बार में छपी ख़बरों को अपनी बहस का आधार बनाया. चौथी दुनिया ने देश को आगाह किया था कि यह कार्ड देश की सुरक्षा के लिए ख़तरनाक है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है.■

फिर भी सत्ता की चाबी ममता के हाथ

पश्चिम बंगाल में छह चरणों में चुनाव होने हैं. पहला चरण नक्सल प्रभावित इलाकों में होगा. वाममोर्चा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कुछ ही नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत ही सोची-समझी रणनीति के साथ इस चुनाव में भी अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं को मजबूती के साथ पकड़ा है.

विनय बिहारी सिंह

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस-सीपीएम का गठजोड़ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अकेली कथित हुंकार अब तक बहुत असरदार नहीं हो पाई है. मतदान में गिनती के दिन रह गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में करीब दस बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं. इसके बाद भी स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. क्योंकि लोग अचानक बढ़ी महंगाई, केंद्र सरकार के कथित अच्छे दिन के दिखाए सपने के टूटने से परेशान और गुस्से में हैं. ऊपर से रेल के टिकट रद्द होने पर बढ़े अप्रत्याशित शुल्क ने इस गुस्से को और बढ़ा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पश्चिम बंगाल में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति की नहीं है, भले ही उनकी सभा में भीड़ हो. रेल बजट में पश्चिम बंगाल को कोई अहमियत नहीं मिली है, जिससे लोग आहत हैं. ले-दे कर केंद्र सरकार की ईस्ट-वेस्ट मेट्रो परियोजना और दक्षिणेश्वर मेट्रो परियोजना है, जिस पर केंद्र सरकार इतरा सकती है. लेकिन, इस परियोजना को ममता बनर्जी ने ही तब शुरू कराया था, जब वे रेल मंत्री थीं. इस तुलना में कांग्रेस-सीपीएम गठजोड़ मजबूत है. उसे 50 से भी अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है.

अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? विधानसभा में भाजपा के सिर्फ एक विधायक हैं, शमिक भट्टाचार्य, जो बशीरहाट दक्षिण सीट से उपचुनाव में जीत कर आए हैं. 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तो आसनसोल सीट से भाजपा के बाबुल सुप्रियो जीत कर संसद में गए. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की दोला सेन को हरा कर यह सीट पाई. लेकिन धीरे-धीरे केंद्र में मोदी सरकार की नीतियों के कारण पश्चिम बंगाल में भाजपा की लोकप्रियता घटी. लेकिन जैसा कि आम चुनावों में होता है, भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित है. उधर फेसबुक पर ममता बनर्जी का कार्टून बनाने के कारण रात भर जेल की हवा खा चुके जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्र ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बेहला (पूर्व) से चुनाव लड़ने की घोषणा की है. वे वहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और मेयर शोभनदेव चटर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे.

इस बीच मतदान के तीन हफ्ते पहले एक चौंकाने वाला स्टिंग वीडियो सामने आ गया. एक प्राइवेट न्यूज चैनल ने तृणमूल कांग्रेस के 11 प्रमुख नेताओं को एक काल्पनिक कंपनी के एजेंट के हाथों रुपए लेते हुए दिखाया है. इस स्टिंग पर विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने टिप्पणियां की है. तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा है कि हमने इस कथित स्टिंग वीडियो को देखा है. इसमें कुछ नहीं है. सीपीएम के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्र ने कहा है कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए या तब तक चुनाव रोक देना चाहिए, जब तक कि इस फेंड़ाफोड़ के महेनजर कोई कदम नहीं उठाया जाता. अगर राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता है, तो वह भी होना चाहिए. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने कहा है कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि जो लोग वीडियो में रुपया ले रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए. भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि स्टिंग आपरेशन से यह साबित हो गया कि तृणमूल कांग्रेस के सारे नेता भ्रष्ट हैं. तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल राय ने कहा कि यह ऐसा वीडियो है जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है. हम इस चैनल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे.

पांच साल पहले ममता बनर्जी ने 34 साल पुरानी वाम मोर्चा सरकार को उखाड़ फेंका था और पूरे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी. पांच साल पहले तत्कालीन वाममोर्चा सरकार ने सिंगुर में किसानों की जमीन, टाटा की नैनो कार फैक्ट्री बनाने के लिए जबरन ले ली थी. किसान जमीन देने के अनिच्छुक थे. वे अपनी जमीन वापस लेना चाहते थे. ममता बनर्जी ने इसे मुद्दा बनाया. उनका आंदोलन काफी व्यापक होता गया. आखिरकार, टाटा को अपनी कार फैक्ट्री सिंगुर से हटा कर गुजरात के साणंद ले जानी पड़ी. यह ममता बनर्जी की जीत और उस समय सत्तारूढ़ वाम मोर्चा की हार थी. मतदाताओं पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा. ममता बनर्जी की छवि अचानक वाम मोर्चा सरकार की उस छवि से बड़ी हो गई, जो उसने पिछले 34 सालों में बनाई थी. सत्ता में आने के बाद किसानों को जमीन वापस करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कानून बनाया. इस कानून का नाम था, द सिंगुर लैंड रिहैबिलिटेशन ऐंड डेवलपमेंट एक्ट 2011. लेकिन इसे अदालत में चुनौती दे दी गई. नतीजा यह हुआ कि न टाटा की फैक्ट्री बनी, न किसानों को जमीन वापस मिली. निश्चित ही सिंगुर में तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई आसान नहीं होगी. पिछले ही दिनों वाममोर्चा सरकार में भूमि सुधार मंत्री रहे अब्दुर रजाक मोल्ला, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए. चुनाव के पहले इसे ममता बनर्जी की भारी कामयाबी कही जा रही है. मोल्ला एक मुखर कम्युनिस्ट नेता रहे हैं और मंत्री रहते हुए उन्होंने कई बार तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उनके तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से राजनीतिक समीकरण बदले हैं.

पश्चिम बंगाल में छह चरणों में चुनाव होने हैं. पहला चरण नक्सल प्रभावित इलाकों में होगा. वाममोर्चा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कुछ ही नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत ही सोची-समझी रणनीति के साथ इस चुनाव में भी अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं को मजबूती के साथ पकड़ा है. पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक समूची आबादी के 27 प्रतिशत है. मालदा और मुर्शिदाबाद को छोड़ कर सभी जिलों में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं. सन 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में 24.7 मिलियन मुसलमान हैं. सन 2011 के चुनाव में वाममोर्चे को 35 से 40 प्रतिशत वोट मिले थे. लेकिन, तब वाममोर्चा सत्ता में था. 2014 के लोकसभा चुनावों में वाममोर्चा के वोट घट कर 23 प्रतिशत तक आ गए थे. पिछले विधानसभा चुनाव में 294 में से तृणमूल कांग्रेस को 184, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 42, वाममोर्चा के घटकों जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को 40, आल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक को 11, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) को 7, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दो, गोरखा जन मुक्ति मोर्चा को 3, समाजवादी पार्टी को 1, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) को 1, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी (प्रबोध चंद्र) को 1 और स्वतंत्र उम्मीदवारों को दो सीटें मिली थीं. ■

चौखट पर चुनाव और दलदल में दीदी का दल

प्रकाश चण्डालिया

चौखट पर चुनाव न होते तो शायद और बात होती. अब चूंकि महासमर का बिगुल बज चुका है. सभी पार्टियों ने ताल ठोंकना शुरू कर दिया है, तो जाहिर तौर पर सत्तारूढ़ होने के कारण ममता बनर्जी को अपने दल के हर अच्छे-बुरे फैसले में साथ ही रहना है. यह टिप्पणी स्टिंग ऑपरेशन में तृणमूल के 12 हेवीवेट नेताओं की पोल खुलने के बाद ममता बनर्जी को लेकर है.

अब, यह भी सवाल उठ सकता है कि कोई और बात होती तो क्या होता? तो, इसके लिए 16 साल पहले के राजनीतिक इतिहास को खंगालना होगा. 13 मार्च 2001 को तहलका ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को एक लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था. नाम तत्कालीन सरकार के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नाण्डीज का भी आया था. ममता बनर्जी तब एनडीए सरकार में रेल मंत्री भी थीं. तहलका का ऑपरेशन सामने आने के बाद संसद में हंगामा मचा और तब दीदी ने दोनों नेताओं के इस्तीफे की मांग की थी. इस्तीफा न होने की सूरत में दीदी ने एनडीए छोड़ देने की धमकी भी दी थी.

अब उपरोक्त संदर्भ को आज की स्थिति के साथ जोड़ कर देखना चाहिए. दीदी का क्या रूख है? सांसद प्रो. सौगत राय, सुल्तान अहमद और मुकुल राय (तीनों पिछली यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं) के साथ राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री सुव्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, सांसद शुभेन्दु अधिकारी, सांसद डॉ. काकली घोष दस्तीदार, मेयर शोभन चटर्जी, पूर्व परिवहन मंत्री, सारदा कांड में गिरफ्तार मदन मित्र सरीखे लोगों के साथ-साथ एक चहेते पुलिस अधीक्षक मिर्जा द्वारा 5-5 लाख रुपये का रिश्वत लेने का खुलासा एक वेबसाइट नारद डॉट कॉम ने किया है. इस खुलासे के बाद दीदी ने इन सब पर कार्रवाई करने की बजाय बचाव किया है. संसद में सौगत राय और सुल्तान अहमद ने तो सीना तानकर इस ऑपरेशन को विपक्षी दलों का षड्यंत्र करार दिया. दीदी का यह दोयम स्वरूप स्वाभाविक तौर पर उनकी सियासी मजबूरी है. हालांकि दिनेश त्रिवेदी जैसे साफ-सुथरी छवि वाले सांसदों ने मशविरा दिया कि इन नेताओं का बचाव करने की बजाय दीदी को जांच कमेटी बैठानी चाहिए. तृणमूल का उजला चेहरा माने जाने वाले डेरेक ओ ब्रेन ने जिस दंभ के साथ इस कांड पर बयान दिया, वह आने वाले दिनों में पार्टी की छवि को और खराब करेगा.

आनन-फानन में बचावी बयान देकर दीदी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली. अब चुनाव सामने हैं. वाम मोर्चा और कांग्रेस ने पहले ही हाथ मिला लिया है और भाजपा भी दीदी से दूरी बनाए हुए है. ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां तृणमूल पर हर जनसभा में छींटाकशी करेंगी. वाम मोर्चा के 34 साल के शासन को कोसने वाली ममता से वामपंथी सीना तान कर कहेंगे कि उनके लंबे शासन काल में किसी मंत्री पर इस प्रकार खुलेआम रिश्वत लेने का आरोप नहीं लगा. स्वाभाविक तौर पर लोकसभा की एथिक्स कमेटी अथवा अन्य जांच एजेंसियां सीडी की फॉरेंसिक जांच करेंगी ही. पर नारद डॉट कॉम के मैथ्यु सैमुअल की खोजी तबीयत से वास्ता रखने वाले जानते हैं कि उन्होंने कच्ची गोटियां नहीं चली हैं. बेशक उनसे भी लाखों रुपए के जुगाड़ पर पूछा जाएगा, लेकिन इससे दीदी के पैसे लेने वाले नेताओं को आराम नहीं मिलने वाला. देखना है, चंद दिनों में शुरू होने वाले मतदान के दौरान बंगाल के भद्रलोक क्या फैसला लेते हैं. पर इसमें शक नहीं कि विकास और विनाश के मुद्दे को पीछे छोड़ कर इस स्टिंग ऑपरेशन ने प्रचार के केंद्र में अपना स्थान बना लिया है. दीदी का दल दलदल में फंस गया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

टेनिस में डोपिंग का डंक

मुश्किल में शारापोवा

शारापोवा ने अपनी गलती मानते हुए कहा, मैं डोप टेस्ट में नाकाम रही और इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूं. मैंने भारी गलती की और अपने प्रशंसकों को निराश किया. मैंने अपने खेल को शर्मसार किया, जिससे मुझे बेपनाह मोहब्बत है. मुझे पता है कि मुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन मैं इस तरह से अपना करियर ख़त्म नहीं करना चाहती. उम्मीद है कि मुझे दोबारा टेनिस खेलने का मौका मिलेगा.

मुझे मेल्डोनियम नामक दवा के सेवन के लिए फेल किया गया, जिसे मैं स्वास्थ्य कारणों से पिछले 10 सालों से ले रही थी.

तरुण फोर

खिलाड़ियों द्वारा अपनी क्षमता और प्रदर्शन में सुधार के लिए दवाओं और अन्य तरीकों के उपयोग का पुराना इतिहास है. कई नामचीन खिलाड़ियों पर अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के आरोप लग चुके हैं और उनपर इसके लिए प्रतिबंध भी लग चुका है. इस सूची में हाल ही में एक नया नाम रूसी टेनिस स्टार मारिया शारापोवा का जुड़ा है. वह ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दौरान ड्रग टेस्ट में फेल हो गई थीं. हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया कि वह प्रतिबंधित दवा मेल्डोनियम का सेवन करने की दोषी पाई गईं हैं.

विश्व की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी और पांच बार ग्रैंड स्लैम विजेता रह चुकीं मारिया शारापोवा ने कहा, मुझे मेल्डोनियम नामक दवा के सेवन के लिए फेल किया गया, जिसे मैं स्वास्थ्य कारणों से पिछले दस सालों से ले रही थी. मारिया ने कहा कि विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी की प्रतिबंधित दवाओं की सूची में इस साल हुए बदलाव के कारण उनसे यह गलती हुई. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ अस्थायी तौर पर निलंबन की सजा सुना सकता है. इस मामले में पहली बार असफल होने वाले खिलाड़ियों पर आमतौर पर दो साल का प्रतिबंध लगाया जाता है. शारापोवा ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि मैं डोप टेस्ट में नाकाम रही और इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूं. मैंने भारी गलती की और अपने प्रशंसकों को निराश किया. मैंने अपने खेल को शर्मसार किया जिससे मुझे बेपनाह मोहब्बत है. मुझे पता है कि मुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन मैं इस तरह से अपना करियर खत्म नहीं करना चाहती. उम्मीद है कि मुझे दोबारा टेनिस खेलने का मौका मिलेगा. मेल्डोनियम को वाडा की प्रतिबंधित लिस्ट में डालने का निर्णय 16 सितंबर 2015 में लिया गया और यह 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में आया है. लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी माने जाने वाली शारापोवा ने क्या यह गलती अनजाने में की या जानकारी में? लेकिन शारापोवा ने खुद ही कहा है कि मेल्डोनियम वाडा की प्रतिबंधित दवाओं की लिस्ट में 1 जनवरी 2016 से ही आई है, जबकि वह इसका इस्तेमाल 2006 से कर रही हैं और इसलिए वह एक लीगल दवा ले रही थीं न कि कोई प्रतिबंधित दवा. शारापोवा ने यह भी कहा है कि उन्हें इसके प्रतिबंधित दवाओं की लिस्ट में होने के बारे में भी कुछ नहीं पता था. हालांकि एक बात पर फिर भी सवाल उठाए जा सकते हैं कि जब वाडा ने रूस ड्रग एजेंसी को मेल्डोनियम के प्रतिबंधित दवाओं के लिस्ट में शामिल किए जाने की जानकारी सितंबर 2015 में ही दे दी थी तो आखिर क्यों शारापोवा को ये बात नहीं बताई गई? रूसी ड्रग एजेंसी ने अपने खिलाड़ियों को इस महत्पवूर्ण जानकारी से महरूम क्यों रखा? अगर रूसी ड्रग एजेंसी इस बात की जानकारी अपने एथलीट्स को दे देती तो शायद शारापोवा बैन से बच जातीं. खैर फिलहाल शारापोवा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है. उनका पक्ष सुनकर ही उनके टेनिस खेलने पर प्रतिबंध लगाएगी. लेकिन प्रोफेशनल खिलाड़ियों का इस तरह का लापरवाह रवैया हैरानी में जरूर डालता है कि क्या सूचना प्रौद्योगिकी के युग में खिलाड़ियों के पास इस तरह की गलती करने की गुंजाइश है इसका जवाब है नहीं क्योंकि खिलाड़ी द्वारा जाने-अनजाने में की गई एक गलती उसके करियर को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है.■

feedback@chauthiduniya.com

क्या है मेल्डोनियम

मेल्डोनियम का इस्तेमाल हार्ट अटैक और सीने में दर्द के लिए किया जाता है. यह दवा लात्विया में बनाई जाती है. लेकिन यह दवा अमेरिका में प्रतिबंधित है. इसका उपयोग इस्कीमिया (शरीर के कुछ हिस्सों में खून के सही प्रवाह न होने) के इलाज के लिए किया जाता है. लेकिन माना जाता है कि इस दवा के उपयोग से खून का प्रवाह बढ़ जाता है जो खिलाडियों में एक्सरसाइज की क्षमता बढ़ा देता है. वाडा को एथलीट्स द्धारा इस दवा का उपयोग उनके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए किए जाने के प्रमाण मिले हैं.■

क्या है वाडा

वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, फ्रेंच, (वाडा) अंतरराष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए बनाई गई एक विश्वस्तरीय स्वतंत्र संस्था है. अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्धारा वाडा की स्थापना 10 नवंबर, 1999 को स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में की गई थी. यह संस्था विश्व भर में वैज्ञानिक शोध, एंटीडोपिंग के विकास की क्षमता में वृद्धि और दुनिया भर में वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड पर अपनी निगाह रखती है. वाडा हर साल प्रतिबंधित दवाओं की सूची जारी करता है, जिनके विश्व के तमाम देशों में खेलों के दौरान प्रयोग पर रोक होती है. पहली जांच में ही दोषी पाए जाने पर खिलाड़ी पर वाडा सभी खेल प्रतियोगिता में दो वर्षों तक भाग लेने पर प्रतिबंध लगा सकती है. हालही के वर्षों में वाडा खेलों में ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर काफी सक्रिय है. वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड का अनुपालन पहली बार 2004 के एथेंस ओलंपिक में किया गया था. विश्व के लगभग 600 खेल संस्थाओं ने ड्रग्स से जुड़ी संहिता को स्वीकार किया है. अभी दुनिया में वाडा से मान्यता प्राप्त 35 प्रयोगशालाएं हैं, जहां ड्रग्स लेने वाले नमूनों की जांच और उसे रोकने के लिए अनुसंधान होते हैं. दिल्ली में भी वाडा से मान्यता प्राप्त एक प्रयोगशाला है.■

प्रदीप सांगवान

डोपिंग और भारतीय खिलाड़ी

राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की चार गुणा 400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक विजेता टीम की सदस्य सिनी जोस समेत पांच भारतीय महिला एथलीट राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) के डोप टेस्ट में विफल रही थी. 400 मीटर रिले की स्वर्ण विजेता टीम की मनदीप कौर और एक अन्य एथलीट जौना मुर्मू शामिल थीं. इन सातों एथलीटों को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया था. भारतीय खिलाड़ी भारोत्तोलक सनामाचा चानू नाडा भी डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई थी. चानू की जांच में प्रतिबंधित पदार्थ मिथाइल हेक्सानिएमाइन लेने के बारे में पता चला था जो 2004 एथेंस ओलंपिक में पकड़े जाने के बाद यह उनका दूसरा अपराध था. आईपीएल खिलाड़ी प्रदीप सांगवान पर डोपिंग का आरोप लगा था. बायें हाथ के तेज गेंदबाज प्रदीप पर रैंडम डोप परीक्षण में प्रतिबंधित दवा के सेवन के दोषी पाए जाने के बाद डोपिंग का डंक लगा था.■

भारतीय खिलाड़ी भारोत्तोलक सनामाचा चानू नाडा भी डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई थीं. चानू की जांच में प्रतिबंधित पदार्थ मिथाइल हेक्सानिएमाइन लेने के बारे में पता चला था. 2004 एथेंस ओलंपिक में पकड़े जाने के बाद यह उनका दूसरा अपराध था.

डोपिंग के दोषी खिलाड़ी

शोएब अख्तर

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी प्रतिबंधित दवा लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं. अख्तर अक्टूबर 2006 में नेनड्रोलेन लेने के विवाद में फंस चुकेहैं. अख्तर पर पीसीबी ने 2 वर्ष के लिए बैन लगाया था.■

आंद्रे आगासी

अमेरिकी टेनिस स्टार रहे आंद्रे आगासी ने अपनी आत्मकथा ओपन में माना था कि वह बैन से बचने के लिए क्रिस्टल मेथ का उपयोग करते रहे हैं. एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स (एटीपी) ने इस बात पर कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया था, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप वापस ले लिए गए थे.■

रियो फर्डिनेंड

19 दिसंबर 2003 को पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर रियो फर्डिनेंड पर प्रतिबंधित दवा लेने के आरोप में आठ महीने का प्रतिबंध लगाया गया था. इसके साथ ही फुटबॉल एसोसिएशन ने उन पर 50 हजार ब्रिटिश पाउंड का भी जुर्माना लगा था. फर्डिनेंड बैन केकारण 2004 का यूरोपियन चैंपियनशिप नहीं खेल पाए थे.■

डिएगो माराडोना

1994 में अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार डिएगो माराडोना भी प्रतिबंधित दवा लेने के आरोप में फंस चुके हैं. अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने माराडोना को ऐसी दवा लेने पर अपनी विश्वकप टीम से निकाल दिया था.■

मार्टिना हिंगिस

2007 में पूर्व विंबलडन चैंपियन मार्टिना हिंगिस ने घोषणा की थी कि कोकीन के एक मेटाबोलाइट बेनजोलेकगलिन लेने के आरोप में उनकी जांच चल रही है. हालांकि उनका यूरीन सैंपल कोकीन की पुख्ता जांच के लिए आवश्यक मात्रा से आधा ही था. फिर भी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने मार्टिना पर दो साल का बैन लगा दिया था. मार्टीना अभी भी टेनिस में सक्रिय हैं और सानिया मिर्जा के साथ दुनिया की नंबर एक महिला युगल टेनिस खिलाडी हैं.■

लांस ऑर्मस्ट्रॉन्ग

सात बार के टूर डे फ्रांस विजेता लांस ऑर्मस्ट्रॉन्ग ने माना था कि वह प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन करते रहे हैं. यूनाटेड स्टेट ऐंटी डोपिंग एजेंसी ने ऑर्मस्ट्रॉन्ग पर यह आरोप लगाया था, जिसे उन्होंने बाद में स्वीकार कर लिया था. एजेंसी ने वर्ष 2009-2010 में ऑर्मस्ट्रॉन्ग के ब्लड सेंपल केआधार पर यह नतीजा निकाला था.■

शेन वॉर्न

ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर और तेज गेंदबाज शेन वॉर्न दुनिया के सबसे कामयाब गेंदबाजों में से एक रहे हैं. फरवरी 2003 में विश्व कप की शुरुआत से बस एक दिन पहले वॉर्न को प्रतिबंधित ड्रग डियूरेक्ट्रिक के सेवन का दोषी पाया था. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की एक समिति ने वॉर्न पर एक वर्ष का बैन लगाया था.■

असाफा पावेल

2013 में जमैका केस्प्रिटंर असाफा पावेल पर प्रतिबंधित दवा ऑक्सिलोफ्रिन लेने के आरोप में 18 महीने का बैन लगा दिया गया था. जून 2005 से मई 2008 तक पावेल के नाम 100 मीटर की दौड़ का विश्व कीर्तिमान था. अपील के बाद पावेल से बैन हटा लिया गया था.■

सिंधु रत्न अवॉर्ड 2016

21 हस्तियां होंगी सम्मानित

सिंधु रत्न अवॉर्ड-2016 समारोह में पत्रकारिता, मनोरंजन, धर्म, सामाजिक-शैक्षिक-शासकीय सेवाओं से जुड़े मनीषियों का स्वागत-सम्मान करने के लिए देश की कई नामचीन हस्तियां समारोह में हिस्सा लेंगी.

आगामी 31 मार्च को फिल्म सिटी नोएडा में आयोजित होने वाले सिंधु रत्न अवॉर्ड-2016 समारोह में देश की उन चर्चित शख्सियतों का सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने अपने सद्कार्यों के माध्यम से न सिर्फ़ समाज के सामने एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया, बल्कि अपने निजी एवं सामाजिक जीवन में संघर्ष और सफलता के नए आयाम रचे. पत्रकारिता, मनोरंजन, धर्म, सामाजिक-शैक्षिक-शासकीय सेवाओं से जुड़े इन मनीषियों का स्वागत-सम्मान करने के लिए देश की कई नामचीन हस्तियां समारोह में हिस्सा लेंगी.

सिंधु रत्न अवॉर्ड-2016 से सम्मानित होने वाली शख्सियतों के नाम निम्नवत् हैं:- पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश श्री ओम प्रकाश, वरिष्ठ कवि एवं राज्यमंत्री श्री सुनील जोगी, वरिष्ठ न्यायाधीश श्री चन्द्रभाल श्रीवास्तव सुकुमार, फिल्म निर्माता प्रेम प्रकाश, दीपक तंवर, देवेंद्र (डीएनए न्यूज एजेंसी), फिल्म अभिनेता जैद हाशमी, शुभ जोशी, मुश्ताक़ खान, पंकज बेरी, अभिनेत्री पाखी हेगड़े, अर्जुमन मुगल, विधान परिषद सदस्य श्री सुनील सिंह साजन, पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश यादव, महेश धाकड़ (दैनिक हिंदुस्तान), श्री कमल शेखरी (हिन्ट मीडिया समूह), पीके बजाज (मायापुरी), मुक्ता रामचंद्रन (ज्वैलरी डिजाइनर), श्री राधे राधे बाबा जी (राष्ट्र संत), महेंद्र सिंह (व्यवसायी) एवं श्री कृष्णवीर सिंह (किसान नेता). समारोह में आने वाली शख्सियतों में श्री संतोष भारतीय (चौथी दुनिया), पार्श्व गायक शंकर साहनी, श्री सुधीर चौधरी (जी न्यूज), श्री वर्धन त्रिवेदी (एबीपी न्यूज), श्री प्रेम शुक्ल (वरिष्ठ पत्रकार), श्री एमएस बिट्टा (सामाजिक कार्यकर्ता), डॉ. रीता बहुगुणा जोशी (विधायक), श्री ऑस्कर फर्नांडीज (पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद), मौलाना कल्बे वारिस (धर्मगुरु), श्री अश्वनी महाजन (स्वदेशी जागरण मंच), महामंडलेश्वर माधवकांत मिश्र एवं योगेश लखानी (ब्राइट) आदि प्रमुख हैं.

आयोजक अमित भाटी के अनुसार, अवॉर्ड समारोह फिल्म सिटी नोएडा में सायं सात बजे से शुरू होगा. निर्देशक दुष्यंत ने बताया कि कार्यक्रम में कई मीडिया समूह सहयोग कर रहे हैं, जिनमें चौथी दुनिया, हिन्ट, मुंबई तहलका, आज का मतदाता, मलिक आउटडोर, द ब्लैक इंक, टीवी आई-9, डीएनए न्यूज, मायापुरी एवं वुमन ऑन टॉप आदि प्रमुख हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com